सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 159, नई दिल्ली । सोमवार, 19 अगस्त 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाले ने ही सही लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया...

03 कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर बना बवंडर
06 तालिबान कुशासन के 3 साल
08 हाथियों के लिए ट्रेन रुकी

अब दिल्ली की सड़कों पर वाहनों के शोर से नहीं होगी परेशानी, ध्वनि अवरोधक तकनीक के इस्तेमाल की तैयारी

सड़कों का शोर नियंत्रित करने के लिए ध्वनि अवरोधक का इस्तेमाल किया जाएगा। सीआआरआई द्वारा विकसित किया गया ये ध्वनि अवरोधक विभिन्न आवृत्ति के आधार पर तैयार किया गया है। सिर्फ सड़क ही नहीं रेलवे और औद्योगिक क्षेत्रों के शोर को भी ये नियंत्रित कर सकेगा। इसकी एक और विशेषता है जिसके आधार पर सीआरआरआई इसके विश्व में पहली बार ऐसी तकनीक विकसित होने का दावा करता है।

संजय बाटला

नई दिल्ली। वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण भी हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। शहरों में तो ध्वनि प्रदूषण सड़कों से घरों तक है। नींद में खलल, कानों के पर्दे को धीमी-धीमी क्षति ये समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं। सड़कों पर वाहनों के इस शोर को रोकने के लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) ने आवृत्ति आधारित ध्वनि अवरोधक तैयार किया है।

संस्थान का दावा है कि यह अवांछित शोर को 95% तक खत्म करने में कारगर है। विकसित होते महानगरों में, वहां के बुनियादी ढांचे में ध्वनि प्रदूषण जैसी प्रमुख खामियां तो उजागर होती ही हैं। इस ध्वनि अवरोधक से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। मुंबई में हिंदमाता फ्लाईओवर पर इस तकनीक का उपयोग होने भी लगा है।

इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन नोएडा-62 मेट्रो स्टेशन और खान मार्केट स्थित अपने जेनसेट के शोर को कम करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल छोटे से हिस्से में इसे दिल्ली स्थिति ईस्ट ऑफ कैलाश मेट्रो स्टेशन पर लगाया गया है।

रेलवे, मेट्रो, राजमार्ग सब जगह उपयोगी

सड़कों का शोर नियंत्रित करने को वैसे कई तरह के अवरोधक हैं लेकिन वर्तमान में सीआआरआई द्वारा विकसित किया गया ये ध्वनि अवरोधक विभिन्न आवृत्ति के आधार पर तैयार किया गया है। सिर्फ सड़क ही नहीं, रेलवे और औद्योगिक क्षेत्रों के शोर को भी ये नियंत्रित कर सकेगा। इसकी एक और विशेषता है जिसके आधार पर सीआरआरआई इसके विश्व में पहली बार ऐसी तकनीक विकसित होने का दावा करता है।

दरअसल इस ध्वनि अवरोधक का डिजाइन विशिष्ट आवृत्तियों निम्न, मध्यम और उच्च के आधार पर तैयार किया गया है। अब तक इस तरह की सुविधा नहीं थी। यह नवाचार रेलवे, मेट्रो, राजमार्ग आदि के लिए सबसे उपयुक्त है, जहां वक्र (टेढ़ी-मेढ़ी) भाग पर ट्रेन की पटरियों से निकलने वाले चीं चीं (इचिंग) का शोर सबसे बड़ी समस्या है।

देश में रेलवे पटरियों के किनारे कई शहर बसे हैं, जहां इसके आसपास के घरों में रहना दुश्वारियों से भरा है। यह उन समस्याओं से भी निजात दिलाने में कारगर होगा। ये उन सड़क चौराहों के लिए भी उपयुक्त है जहां हार्न बजाना सबसे बड़ी समस्या है। बता दें कि रेलवे, राजमार्ग या विमानन लगभग 72% ध्वनि प्रदूषण में योगदान करते हैं।

ध्वनि अवरोधक का न्यूनतम जीवन दो दशक

सामान्य परिस्थितियों में आवृत्ति आधारित शोर अवरोधक का न्यूनतम जीवन दो दशक तक है। इसकी विशेषता है कि इसे पुनः उपयोग किया जा सकता है। स्थापना के दौरान और स्थापना के बाद मानव शरीर पर इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीआरआरआई ने तीनों ध्वनि अवरोधक की तकनीक के लिए 50 लाख रुपये कीमत तय की है।

वहीं, कोई एक लेने पर 25 लाख देना होगा। फिलहाल दो मुंबई और एक विशाखापतनम की कंपनी ने इस तकनीक को खरीदा है। यह ध्वनि अवरोधक आधा मीटर ऊंचा और डेढ़ मीटर चौड़ा है। इसे लगाने के लिए पहले एक लोहे का फ्रेम तैयार किया जाता है। खुली जगह पर इसे कम से कम तीन मीटर ऊंचा लगाने की जरूरत होती है।

दुनिया में पहली बार हमने ऐसी बाधाएं विकसित की हैं जिनके जरिये तीनों तरह के शोर की आवृत्तियों को रोका जा सकता है। अवरोधों को फ्लाईओवर, यातायात चौराहों और रेलवे स्टेशनों पर आसानी से लगाया जा सकता है। वायु प्रदूषण की तरह ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए ऐसे ध्वनि अवरोधकों की आवश्यकता है। – ***नसीम अख्तर, मुख्य विज्ञानी, परिवहन योजना और पर्यावरण, सीआरआरआई***

एक भारतीय नागरिक का अन्य नागरिकों के प्रति जरूरी संदेश

अज्ञानता के कारण लगभग सभी डिफॉल्टर plead guilty करते हैं और कोर्ट को ठोक कर जुर्माना लगाने पर मजबूर होना पड़ता है। कृपया ऐसा न करें। कोर्ट में चालान कॉन्टेस्ट करें। पहले जुर्माने कम थे जिस की वजह से गिल्टी पलीड करना यानी अपना कसूर अदालत में मान लेना समय बचने और परेशानी से बचने के लिए सही था। परन्तु अब ऐसा नहीं है ।अंधाधुंध अपना कसूर मानना अब बहुत मंहगा पड़ेगा। जेल जाने की नोबत भी आ सकती है। इस लिए आंखें खुली रखने की ज़रूरत है। ट्रैफिक के नियमों को पालन करने की आदत डालिये चाहे कोई आप को देख रहा हो या नहीं। बहुत जल्दी जगह जगह कैमरे लग जायेंगे। चालान आपके घर पर या मोबाइल और ईमेल पर आने शुरू हो जाएंगे। ट्रैफिक वालों से झगड़ा करने या वीडियो बनाने का मौका आपको नही मिलेगा। अब भारत के असली नागरिक बन जाएं और कानून का पालन करें वह चाहे आपको सही लगे या गलत। गलत लगे तो अपनी आवाज़ उठाने दें। चालान के आतंक से बचें।

यहां एक पुलिस वाले द्वारा बनाया गया वीडियो भी आपका सही मार्ग दर्शन करेगा। उसे देख लें और आगे बताई बातों पर ग़ौर करें।

1. सख्त कानून समाज की भलाई के लिए बना दिया जाता है पर उसका उपयोग कम समय तक रहता है और दुरुपयोग बढ़ जाता है ।तब वह कानून उपयोगी न होकर नासूर बन जाता है। जैसे दहेज प्रताडना का कानून 498A, रेप, मोलेस्टेशन, पोस्को आदि में बर्डन ऑफ प्रूफ का कानून। ऐसा इसलिए होता है कि पुलिस के पास उसे लागू करने के लिए अपना विवेक प्रयोग करने का विकल्प ही नही रहता और कोर्ट से राहत पाना टेडी खीर हो जाता है। गुनाह साबत होने से पहले ही आरोपित लगभग सज़ा हो जाता है इतनी सज़ा काटने के बाद कोर्ट भी उसे बरी करने की हिम्मत नही करता क्योंकि पब्लिक में सन्देश जज की रिश्वत का जाने का डर रहता है। अब ऐसा ही है नया ट्रैफिक कानून। यदि इसे अंधा धुन्ध लागू किया जाता रहा तो इसकी भी दुर्गति होना लाजमी है।

2. सबसे पहले ज़रूरत है ट्रैफिक पुलिस को अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने की। रस्सी का सांप बनाने की ज़रूरत नही उसे रस्सी ही रहने दें। सबसे बड़ी अज्ञानता है कागज़ात के बारे में जो नई नहीं बहुत पहले से है। दूसरी है चेतावनी की। चालान करने से पहले ज़मीनी हालात को देख कर अपने चेतावनी देकर छोड़ने के अधिकार का ज़रूर प्रयोग करें। सड़क पर खुद भी गाड़ी चला कर देखगें तो violation का सही आकलन करने का मौका मिलेगा। जानने की कोशिश करें कि भीड़ में पीछे से आ रही एम्बुलेंस को किस तरफ से रास्ता देंगे। अब बाकी हालात।

3. सबसे पहले RC - यानी रजिस्ट्रेशन होने का प्रमाण पत्र। ट्रैफिक पुलिस मांगती है ओरिजिन RC केवल यह साबित करने के लिए कि वाहन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में विधिवत रजिस्टर्ड है और यह धारा 39 की अवहेलना करके बिना रजिस्ट्रेशन के तो नहीं चलाया जा रहा। पुलिस को स्पष्ट दिखाई देता है कि वाहन पर रजिस्ट्रेशन नम्बर लिखा है उसे ही सही मानकर वह चालान पर उसका नम्बर लिखती है। आजकल वाहन पर सिक्योरिटी नम्बर प्लेट भी लगी होती है जो रजिस्ट्रेशन होने पर ही प्रमाण के तौर पर अथॉरिटी द्वारा जारी की जाती है। पुलिस का तर्क होगा कि नम्बर तो जाली हो सकता है । यदि ऐसा है तो RC भी तो जाली हो सकती है। पर यह विषय अलग है जालसाज़ी IPC का अलग अपराध है। मौका पर RC न दिखा पाना 39 MVAct का अपराध कतई नहीं है। वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के नही चलाया जा रहा ।यहीं स्पष्ट कर दूं कि धारा 130(1) MVAct के मुताबिक पब्लिक प्लेस पर वाहन चलाने वाले चालक को बावर्दी पुलिस अफसर के मोके पर मांगने पर अपना लाइसेंस DL या कोई चालान पर्ची दिखाना होता है और असल लाइसेंस केंद्र सरकार द्वारा 139 CMVR द्वारा तय किये समय 15 दिन मे दिखाया जा सकता है जब वह अधिकारी उसे यह साबित करने के लिये कि चालक को अथॉरिटी ने वह वाहन चलाने के लिए अधिकृत किया हुआ है, पेश करने की मांग करे। यानि उस अधिकारी द्वारा 130(1) MVAct के तहत नोटिस देना होगा। धारा 130(3) MVAct के तहत वाहन का इन्सुरेंस सर्टिफिकेट रजिस्टरिंग अथॉरिटी द्वारा या मोटर वेहिकल डिपार्टमेंट के अधिकृत अधिकारी द्वारा मांग करने पर दिखाया जाएगा और यदि वह वाहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट भी मंगाया जा सकता है पर यदि ये कागज़ात यानि इन्सुरेंस सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट चालक के पास उस समय नही हैं तब वह नोटिस द्वारा की गई मांग के जवाब में उनकी अटेस्टेड कापियां 15 दिन में दिखा सकता है या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा उस मांग करने वाले अधिकारी को भेज सकता है। धारा 130(4) MVAct के तहत, किसी भी चालक का DL या ट्रासपोर्ट वेहिकल के ये कागज़ भी किसी द्वारा शौकिया नही मंगाए जा सकते नोटिस में कारण दर्ज करना होगा और केंद्र सरकार द्वारा तय समय देना होगा जो 15 दिन है (139 cmvr)

4. धारा 158 MVAct के तहत सार्वजनिक स्थान पर वाहन चला रहे किसी भी वाहन के चालक को बावर्दी पुलिस अधिकारी के मांगने पर वाहन का इन्सुरेंस, RC, DL और यदि वाहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो उसका फ़टिनेस सर्टिफिकेट और परमिट भी पेश करना होता है। यह प्रावधान सड़क पर जा रहे वाहनों को रोक रोक कर कागज़ात मांगने के लिए नही है बल्कि पूरे सेक्शन में बताए गए हालात में केवल वाहन द्वारा एक्सीडेंट करने पर मांगे जा सकते हैं जिसमे किसी की मौत हो जाये या चोट आयी हो। 156(3) MVAct के मुताबिक पुलिस द्वारा दिये गए समय या एक्सीडेंट के बाद 7 दिन से पहले कागज़ न दिखाने पर कागज़ात पेश न करने की इस धारा में convict नही किया जा सकता जिसका मतलब है कि चालान नही बनता, जुर्माना भरने की ज़रूरत नही है। इसलिए चालान का जुर्माना न भरें। चालान कांटेस्ट करें। वकील कर लेने की आदत डालें। पुलिस को अभी इन धाराओं का ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि उन्हें केवल एक जुर्माने का चार्ट दिया जाता है जिसके आधार पर वे मनमाने चालान करते रहते है। वे समय की कमी के कारण Act ठीक से पढ़ और समझ नही पाते। उन्हें गवाही देने कोर्ट जाने की ज़रूरत नही पड़ती। कोर्ट का वकील पसीना निकल देता है। ज्ञात हो कि किसी भी चालान पर कोर्ट में जुर्माना तब तक नहीं हो सकता जब तक चालान करने वाले शिकायतकर्ता अधिकारी और उसके साथ sign करने वाले गवाह पुलिस अधिकारी की गवाही कोर्ट में दर्ज न हो।

5. अब तक आप समझ गए होंगे कि कानून वाहन चालकों के साथ है पर आप जानबूझ कर गुनहगार बनने की जल्दी में रहते हैं ।DL, RC, इन्शुरन्स, परमिट, फिटनेस, PUC दिखाने के लिए संसद ने पूरी समझदारी के साथ 7 दिन से 15 दिन तक के समय का प्रावधान किया है। वह भी केवल अटेस्टेड कापियां। केंद्र सरकार ने डिजिलॉकर App जारी की हुई है जिसमे आप अपने तमाम कागज़ात रख सकते हैं और अधीकृत अफसर के मांगने पर उसमे से दिख सकते हैं। अगर कोई पुलिस अधिकारी उन्हें मानने से इनकार करता है और चालान कर देता है तो वह केंद्र सरकार के आदेश की अवहेलना करता है जो उसकी और उसके अफसरों की नोकरी में छेद होना तय है ।कोर्ट के चालान के साथ लगाने ले लिए कोई ओरिजिनल कागज़ ज़ब्त करना गैर कानूनी है। यह भारत मे रहने वाले भारत के नागरिक और भारत के कानून का अपमान है कि पुलिस वाला उसे चालान नही भुगतने वाला संभावित भगोड़ा अपराधी समझता है क्योंकि धारा 206 MVAct के तहत कोई कागज़ ज़ब्त करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को तभी है जब उसके पास यह मानने का कोई कारण हो कि वह कागज़ जाली है या उसको यह लगे कि चालक चालान भरने कोर्ट नही जाएगा और भगोड़ा हो जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, DL, RC पर दर्ज सूचना जो कि लाइसेंस नम्बर या वाहन नम्बर डालते ही चालान की मशीन की स्क्रीन पर आ जाती है और वेरीफाई हो जाती है पर विश्वास न करने का कोई कारण नज़र नही आता। लोग नोटिस ब्रांच के गैरकानूनी चालानों को तो बिना किसी ज़ब्त कागज़ के और भगोड़ा हुए बिना धड़ाधड़ भरे जा रहे हैं। यह केवल पुलिस की मानसिकता का फर्क और ऊपर के अधिकारियों का डर है जो इस बात की समझ होते हुए भी नीचे के अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी नही करते। सब कुछ हवलदार के जिम्मे छोड़ देते हैं। अब तो लोग SMS पर भी कोर्ट चले जाते हैं। सब DL, RC के साथ मोबाइल लिंक है। डर किस बात का है ? भारत के नागरिक का सम्मान करें !

6. लाइसेंस जेब मे न होना 3/181 MVAct का अपराध नही। लाइसेंस कभी बना ही न होना इसमे आ सकता है। इसका दुरुपयोग बन्द करें। कॉपी या मोबाइल में फ़ोटो को माने और अपने ऑनलाइन डेटा से वेरीफाई कर लें। जिसको एक बार लाइसेंस जारी हो गया वह सेक्शन 3 का violator नहीं चाहे लाइसेंस उसके जेब मे हो या न हो।

7. इन्सुरेंस सर्टिफिकेट पेश करने के लिए 7 दिन का समय दे जो कानून में है। आजकल पालिसी बाजार से पालिसी बनती है सब के मोबाइल में होती है ।देख लें और शक है तो न लाइन वेरीफाई कर ले। फिर भी यकीन ना आये तो उस digitally signed इन्सुरेंस का प्रिंट मंगा लें।

8 PUC के बारे में नियम 115 CMVR को अच्छी तरह पढ़ ले। ये नियम polluting व्हीकल्स के लिए बने है अगर कोई व्हीकल पॉल्युशन इंस्पेक्टर द्वारा checking पर तय मात्रा से ज़्यादा pollute करते पाया जाता है केवल उसी का चालान होता है जो 15 दिन के अंदर वह उसे ठीक करवा कर उसका PUC पेश न कर दे । अन्य केस में suspected व्हीकल को नोटिस होता है उसे भी 15 दिन में PUC पेश करना है। सड़क पर चेकिंग बन्द करने के लिए वाहन का emission चेक कर पर PUC बनवाने के लिए स्टेशन अधिकृत किये गए। नये वाहन का PUC कम्पनी 2 साल तय करती है उसके पास अलग से puc होना जरूरी नही। पर अनजान पुलिस वालों के डर से लाखों गाड़ियां PUC की लाइन में हैं। PUC का कागज़ न होना 190(2) MVAct का अपराध नहीं। वह केवल pollute करते पाए जाने पर है। CNG गाड़ियों को PUC की क्या ज़रूरत है ? उनको क्यों माफिया द्वारा चलाये जा रहे PUC केंद्रों की लाइन में लगने पर मजबूर किया जा रहा है ? क्यों जरूरी है दिल्ली में 3 महीने में PUC renew करवाना ? मांगने पर तय समय मे कागज़ न दिखा पाना केवल 177 MVAct के तहत दण्डनीय है क्योकि वह 139 CMVR की violation है चाहे वह DL, RC, Insurance, Permit, Fitness या PUC में से कुछ भी हो। चालान नहीं उन्हें पेश करने का नोटिस बनता है जिस पर जुर्माना नही देना है।

9. रूल 139 CMVR में स्पष्ट कर दिया गया है की Central Government ने बावर्दी सक्षम अधिकारी के मांगने पर DL, RC, Permit, फिटनेस, Insurence आदि पेश करने का समय 15 दिन तय किया है। इसलिए जुर्माना भरना है तो केवल विज़बिल violation का भरें। कागज़ न होने का नही। Red Light Jump , लेन में न चलना, ओवरस्पीड, dangerous driving , बिनहेलमेट , बिना सीट बेल्ट, तीन सवारी, नाबालिग को वाहन चलाने देना आदि तो भरना ही पड़ेगा पर इनकी भी सरकार द्वारा तय राशि ही भरना।

8. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना CMVR के रुल 21(25) के तहत nuisance और पब्लिक की जान को खतरे में डालना हैं जिसकी violation 177 MVAct के तहत दण्डनीय अपराध है न कि 184 MVAct के तहत जिसमे कि पुलिस आपका गलत चालान करती है। इस चालान का दुरुपयोग बहुत हो रहा है। जिस violation की धारा कानून में स्पष्ट दे रखी हो उसे तोड़ मरोड़ कर संगीन बनाना नादिरशाही है जो भारत मे शोभा नही देता और संविधान का मज़ाक है।

9. यह सब कानून पर आधारित है इससे तमाम को अवगत कराएं ताकि उन के दिमाग से नए ट्रैफिक नियमों का बेवजह खोफ कम हो जाये और अच्छे के लिए की गई amendments अच्छे नतीजे लेकर डिसिप्लिन ला सके। पुलिस को शिक्षित करने का अधिकारी अभियान चलायें। खुल कर इसे शेयर करें ताकि पुलिस के सक्षम अधिकारियों तक भी पहुंचे। हरयाणा के DGP साहब ने तो अपने स्टाफ को बिना किसी विज़बिल violation के वाहन रोकने के लिए सख्त शब्दों में मन किया है ।उनका सन्देश वायरल हो चुका है।

10. ट्रैफिक लाइट ठीक न रखने, क्रासिंग पर रेहड़ियां लगवाने, फुटपाथ पर एनक्रोचमेंट खत्म न करने, सड़क के बीच और सड़क के किनारे खड्डे न भरने के लिए किस किस पर कितना कितना जुर्माना होगा अगली पोस्ट में पढ़ना। पैदल चलने वालों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। फुटपाथ के सिग्नल ठीक होते ही उन पर भारी चालान की गाज गिरने वाली है। discipline में आ जाएं ! जनहित में।

डीटीसी ए.एम.सी क्या है, विस्तार से जानें

बस को चलाने में एएमसी का क्या रोल है। यूनियन ने ए.एम.सी. के बारे में बारीकी से अध्ययन किया। आज की तारीख में डीटीसी विभाग में ए.एम.सी.शब्द का बहुत महत्व है डीटीसी के बेड़े में जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें और जे.बी.एम.की ब्लू बसें आई है यह सभी ए. एम.सी. के तहत चल रही है। इन बसों का सभी रख रखाव, देख-रेख, तेल पानी, साफ सफाई, डेंट पेंट और प्राइवेट ड्राईवर इन सभी की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी की है। ए. एम.सी. एक ऐसा पार्ट है जो डीटीसी विभाग ने अपने पास रखकर बहुत ही बढ़िया बेहतरीन काम किया है और यह कबीले तारीफ की बात है। डीटीसी विभाग इन प्राइवेट बसों के मालिकों को 1 किलोमीटर का लगभग 70 रुपए देते है मतलब की एक बस एक दिन में 220 किलोमीटर कम से कम चलती है, 220×70=15400 इतने पैसे एक बस के चलाने का डीटीसी विभाग प्राइवेट मालिकों को प्रतिदिन देता है। एक साल में एक बस को लगभग 72 हजार किलोमीटर चलाना है यानी डीटीसी द्वारा एक साल में प्रति बस कम से कम 72000x70 =50,40,000 रुपए देने ही है। यानी 15 साल में 7,56,00,000 रू। ड्राइवर पर मानसिक तनाव दवाब हों या वो कैसे भी चलाए यह डिपो मैनेजर की जिम्मेदारी भी है। दिल्ली में जितने भी डिपो ए.एम.सी.के तहत आते है उसमें साफ लिखा है कि बस अगर अपनी आउटशेडिंग समय से 15 मिनट से ज्यादा लेट होती है तो 100 रू जुर्माना, 20 मिनट लेट तो 200 रू और 25 मिनट लेट तो 300 रू जुर्माना और इसी आधार पर यह जुर्माना बढ़ता चला जाएगा, ए.एम.सी.के तहत बस बिल्कुल पूरी तरह से साफ सुथरी और कोई भी चीज खराब नही होनी चाहिए यह एक एक चीज को देखना डीटीसी आर.एम.डिपो प्रबंधक (वर्कशॉप) का काम है पर कोई भी ए.एम.सी नियम का पालन नही करता है जबकि डीटीसी विभाग तो हर एक चीज की मेनेटेंस का पैसा प्राइवेट कंपनी को दे रहा है। **बस की देख रेख में क्या क्या देखा जाता है** हेड लाइट, इंडकटेर, पार्किंग लाइट, स्पीड मीटर, बैट्री वाइपर, जैसे (ईटीसी) के अंदर की सभी बसों की अंदर की सीटें बिल्कुल साफ सुथरी, बस के अंदर बाहर से सभी शीशे बिल्कुल साफ होने चाहिए एक दाग भी लगने पर प्राइवेट कम्पनी को पेनेल्टी है, कोई वेल्डिंग, कोई भी चीज खुल्ली नही होनी चाहिए, कोई भी नट या से इस्क्रो ढीला नही होना चाहिए, इत्यादि चीजें एएमसी में लिखी गई है, डीटीसी के फोरमैन वर्कशॉप को अपनी ड्यूटी का सही इस्तेमाल करना होगा, बस में जो भी डिफेक्ट होगा उनको अपने रजिस्टर में अंकित करना होगा, यूनियन के सभी सक्रिय सदस्य साथी सड़को पर ही रहते हैं और किसी ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दी तो यह आप की अपनी जिम्मेदारी होगी, दिल्ली की जनता को **एएमसी.**के बारे में पता हो जिससे वह भी बस की कम्मियो की शिकायत कर अपना दायित्व निभा सके।

पत्रकार हंसराज

ऑटो चालकों के बीच नई ऊर्जा से आटो संवाद की होगी शुरुआत : गोपाल राय

सुषमा रानी

नई दिल्ली। 18 अगस्त दिल्ली सरकार में मंत्री और प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने शनिवार को ऑटो संवाद अभियान चलाने का एलान किया था। ऑटो संवाद अभियान को लेकर गोपाल राय ने कहा कि ऑटो विंग का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन 20 अगस्त से शुरू होगा। इस अभियान का संचालन एक 14 सदस्यीय कमेटी करेगी। दिल्ली के ऑटो चालक अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काम को जनता तक पहुंचाएंगे। साथ ही दिल्ली का काम रोकने की भाजपा साजिश का सच उजागर करेंगे। इसके लिए ऑटो चालक केजरीवाल के प्रतिनिधि बनेंगे और पूरी दिल्ली के ऑटो स्टैंड पर रोजाना ऑटो संवाद अभियान चलाकर लोगों से बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल को जेल में भी ऑटो चालकों की बड़ी चिंता है। मेरा दिल्ली के ऑटो चालकों से अनुरोध है कि भी आप भाजपा के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आप चुनाव में चुप बैठ गए और केजरीवाल सरकार चली जाएगी तो आपको मुफ्त मिल रही बिजली-पानी, स्कूल- अस्पताल की दोगुनी कीमत वसूली जाएगी।

गोपाल राय ने आगे कहा कि जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई तो पूरी दिल्ली में हमारे ऑटो चालक भाइयों को सम्मान मिलने लगा। लोग जानने लगे कि ऑटो चालकों की भी कोई इज्जत होती है। पहले कोई ऑटो चालकों की सुनने वाला नहीं था। सभी पार्टियों की सरकारें बनीं, लेकिन केजरीवाल के नेतृत्व में ''आप'' सरकार ने ऑटो चालकों का जो सम्मान किया है, इससे पहले किसी पार्टी ने नहीं दिलाया। अरविंद केजरीवाल ने जेल से संदेश दिया है कि सभी पदाधिकारी दिल्ली के सभी 511 ऑटो स्टैंड पर केजरीवाल सरकार के सारे कामों को गिनवाते हुए पूरी दिल्ली में ऑटो संवाद करें। जब तक मैं जेल के अंदर हूं, हमारे सभी ऑटो वाले भाई मिलकर मेरा प्रतिनिधि बनकर ऑटो स्टैंड पर लोगों से संवाद करेंगे और सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएंगे। 20 अगस्त से हमें पूरी दिल्ली के अंदर ऑटो संवाद अभियान शुरू करना है। इसमें हम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दिल्ली सरकार द्वारा किए गए कामों को लोगों तक पहुंचाएंगे।

श्रावण पूर्णिमा : शिव भक्ति का पुण्य पाएं

हिंदू धर्म में सावन माह की पूर्णिमा बहुत ही पवित्र व शुभ दिन माना जाता है। सावन पूर्णिमा की तिथि धार्मिक दृष्टि के साथ ही साथ व्यावहारिक रूप से भी बहुत ही महत्त्व रखती है। इस माह को भगवान शिव की पूजा-उपासना का महीना माना जाता है। सावन में हर दिन भगवान शिव की विशेष पूजा करने का विधान है। इस प्रकार की गई पूजा से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस माह की पूर्णिमा तिथि इस मास का अंतिम दिन माना जाता है। अतः इस दिन शिव पूजा व जल अभिषेक से पूरे माह की शिव भक्ति का पुण्य प्राप्त होता है

महत्त्व

प्राचीनकाल में आज के दिन ब्राह्मण अपने यजमानों को रक्षा का धागा अर्थात राखी बांधते थे और साधु-संत एक ही जगह पर चार मास रुक कर अध्ययन-मनन और पठन-पाठन प्रारंभ करते थे। ऋषि-मुनि और साधु-संन्यासी तपोवनों से आकर गांवों व नगरों के समीप रहने लगते थे और एक ही स्थान पर चार मास तक रहकर जनता में धर्म का प्रचार (चातुर्मास) करते थे। इस प्रक्रिया को श्रावणी उपक्रम कहा जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है, अतः इस दिन पूजा-उपासना करने से चंद्रदोष से मुक्ति मिलती है। श्रावणी पूर्णिमा का दिन दान, पुण्य के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसीलिए इस दिन स्नान के बाद गाय आदि को चारा खिलाना, चींटियों, मछलियों आदि को दाना खिलाना चाहिए। इस दिन गोदान का बहुत महत्त्व ग्रंथों में बतलाया गया है। श्रावणी पर्व के दिन जनेऊ पहनने वाला हर धर्मावलंबी मन, वचन और कर्म की पवित्रता का संकल्प लेकर जनेऊ बदलता है। इस दिन ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देना और भोजन कराया जाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा का विधान है।

व्रत व पूजा विधि

श्रावण मास की पूर्णिमा पर वैसे तो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पर्वों के अनुसार पूजा विधियां भी भिन्न होती हैं, लेकिन चूंकि इस दिन रक्षासूत्र बांधने या बंधवाने की परंपरा है तो उसके लिए लाल या पीले रेशमी वस्त्र में सरसों, अक्षत रखकर उसे लाल धागे (मौली या कच्चा सूत हो तो बेहतर) में बांधकर पानी से सींचकर तांबे के बर्तन में रखें। भगवान विष्णु, भगवान शिव सहित देवी-देवताओं, कुलदेवताओं की पूजा कर ब्राह्मण से अपने हाथ पर पोटली का रक्षासूत्र बंधवाना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण देवता को भोजन करवाकर दान-दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। साथ ही इस दिन वेदों का अध्ययन करने की परंपरा भी है। इस पूर्णिमा को देव, ऋषि, पितर आदि के लिए तर्पण भी करना चाहिए। व्रत का पालन किया जाए तो वर्ष भर वैदिक कर्म न करने की भूल भी माफ हो जाती है।

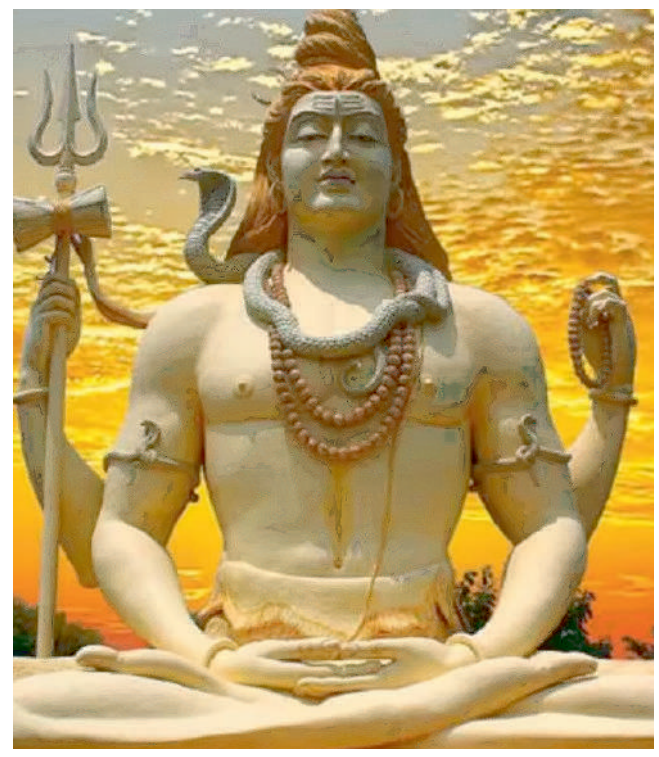

रक्षा बंधन पर भद्रा का साया, जानिए क्या है शुभ मुहूर्त

इस बार भी रक्षाबंधन पर्व पर भद्रा का साया रहेगा। इस बार रक्षाबंधन श्रावणी का पर्व 19 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन रक्षाबंधन पर सात घंटे 39 मिनट तक भद्रा का साया रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को श्रावणी व रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। उसमें भद्रा का साया न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। शास्त्रों के मुताबिक रक्षा सूत्र बंधन का कार्य भद्रा रहित शुभ मुहूर्त काल में ही होना चाहिए। भद्रा काल को अशुभ माना गया है। इस कारण से इस मुहुत काल में रक्षा बंधन का विधान निषेध बताया गया है।

इस बार रक्षाबंधन पर सात घंटे से अधिक समय तक भद्रा का साया रहेगा। साथ ही इस दौरान श्रावणी कर्म भी निषेध रहेगा। इस बार रक्षाबंधन पर सुबह 05:53 से अपराह्न 01: 32 तक भद्रा रहेगी। इस दौरान भद्रा का वास पाताल लोक में बताया गया है। कुछ ज्योतिष के मानने वालों का कहना है कि पाताल की भ्रदा का विशेष महत्व नहीं होता, इसकों नजरअंदाज भी किया जा सकता है। अर्थात यदि कोई भद्रा काल में रक्षा सूत्र बांधता या बंधवाता है तो कोई हानि नहीं है। यदि मुहुर्त के हिसाब से रक्षा सूत्र बंधवाया जाए जो विशेष फलदायी होता है। ज्योतिषाचार्य डा. प्रदीप जोशी के अनुसार रक्षा बंधन पर भद्रा काल अवश्य रहता है। केवल इसका समय आगे-पीछे रहता है। इस बार भद्रा पाताल लोक में होने के कारण पर्व को अधिक प्रभावित नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि भद्राकाल के बाद दोपहर में रक्षा सूत्र बांधना, बंधवाना उत्तम रहेगा।

अपनेपन का प्रतीक है रक्षाबंधन का पर्व

रमेश सर्राफ धमोरा

भारत में रक्षाबंधन के पवित्र पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रिश्तों में मिठास, विश्वास और प्रेम बढ़ाने वाला पर्व माना गया है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, और उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं।

अपनेपन का प्रतीक है रक्षाबंधन का पर्व

भारत में रक्षाबंधन के पवित्र पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रिश्तों में मिठास, विश्वास और प्रेम बढ़ाने वाला पर्व माना गया है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, और उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दौरान भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है, और क्षमता के अनुसार उसे उपहार देता है। रक्षाबन्धन का पर्व भाई-बहिन के स्नेह का प्रतीक देश का एक प्रमुख त्यौहार है। रक्षाबन्धन पर्व में रक्षासूत्र यानि राखी का सबसे अधिक महत्व है। इस पर्व के दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाये जाने के कारण इसे श्रावणी पर्व भी कहते हैं। इस दिन ब्राह्मण, गुरु द्वारा भी राखी बांधी जाती है।

हिन्दू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षासूत्र बांधते समय पण्डित संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। जिसमें रक्षाबन्धन का सम्बन्ध राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। यह श्लोक रक्षाबन्धन का अभीष्ट मन्त्र है।

येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः
तेन त्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचलः

इस श्लोक का अर्थ है जिस रक्षासूत्र से महान शक्तिशाली दानवेन्द्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूं। तुम अपने संकल्प से कभी भी विचलित मत होना।

रक्षाबंधन का त्योहार कब शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता। लेकिन भविष्य पुराण में इस पर्व का वर्णन मिलता है। जब देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हुआ। तब देवताओं पर दानव हावी होने लगे। देवराज इन्द्र ने घबरा कर देवताओं के गुरू बृहस्पति से मदद की गुहार की। वहां बैठी इन्द्र की पत्नी इन्द्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मन्त्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। लोगों का विश्वास है कि इन्द्र इस लड़ाई में इसी धागे की मन्त्र शक्ति से ही विजयी हुए थे। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। यह धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह समर्थ माना जाता है।

विष्णु पुराण के एक प्रसंग में कहा गया है कि श्रावण की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर वेदों को ब्रह्मा के लिये फिर से प्राप्त किया था। हयग्रीव को विद्या और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। महाभारत में ही रक्षाबन्धन से सम्बन्धित कृष्ण और द्रौपदी का एक और वृत्तान्त भी मिलता है। जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी तर्जनी में चोट आ गई। द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी फाडकर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी। यह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। कृष्ण ने इस उपकार का बदला बाद में चीरहरण के समय उनकी साड़ी को बढ़ाकर चुकाया। कहते हैं परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना रक्षाबन्धन के पर्व में यहीं से प्रारम्भ हुई।

महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूं। तब भगवान कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिये राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि राखी के इस रेशमी धागे में वह शक्ति है जिससे आप हर विपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। इस समय द्रौपदी द्वारा कृष्ण को तथा कुन्ती द्वारा अभिमन्यु को राखी बांधने के कई उल्लेख मिलते हैं।

स्कन्ध पुराण, पद्मपुराण और श्रीमद्भागवत में वामनावतार नामक कथा में रक्षाबन्धन का प्रसंग मिलता है। दानवेन्द्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया तो इन्द्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेष धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। गुरु के मना करने पर भी राजा बलि ने तीन पग भूमि दान कर दी।

राखी और रक्षाबंधन

ऐसा नहीं हैं कि
रक्षा सूत्र बाँधने से ही
राखी की इतिश्री हो जाती.
रखना होता है,
एक-दूसरे का खयाल,
पूछना होता है हाल-चाल.
सुख में कम और
दु:ख में ज्यादा
इस स्नेह बंधन की,
होती मजबूत पहचान.
परिस्थितियाँ ही लेती हैं
इस रिश्ते की परीक्षा,
तू अमीर, मैं गरीब का
ये सामाजिक आवरण,
आपसी प्रेम ही करता
इसका आंकलन, वरण.
सिर्फ़ भाई से ही रक्षा का
वचन न लेना बहना.
अब तो इस नवयुग में,
बहन भी हो गईं है सक्षम.
रख लेना उसका भी ध्यान,
यदि हो वह भाई अक्षम.
होगा तभी सार्थक,
राखी और रक्षाबंधन.

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इंदौर (मध्य प्रदेश)
98260 25986

भारत के सबसे खूबसूरत हैं ये 7 वॉटरफॉल, घूमने के लिए बनाएं प्लान

दिव्यांशी भदौरिया

मानसून के सीजन में घूमने का अलग ही मजा होता है। गर्मी से ठंडक मिलने के साथ-साथ बारिश का मजा लेना काफी मजेदार होता है। अगर आप भी कहीं घूमने का प्लान बना रहें तो भारत के सबसे अद्भुत झरने जरुर देखें। आइए जानते हैं कौन से 7 झरने सबसे खूबसूरत है। जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं।

गौरतलब है कि घाटियों में बहुत ऊंचाई से गिरते पानी को देखना हमेशा ही लुभावना होता है, जिससे मनमोहक झरने बनते हैं। हरे-भरे परिदृश्यों पर नाचता झागदार पानी दुनिया भर में एक आश्चर्यजनक नजारा बनाता है। एक तरफ नियाग्रा फॉल्स को दुनिया भर में सबसे बड़े झरने का खिताब हासिल है, वहीं भारत में भी अपने ऐसे ही अविश्वसनीय झरने हैं जो उतने ही विस्मयकारी है। इन राजसी झरनों के सामने खड़े होकर आप उनकी प्राकृतिक भव्यता के सामने खुद को रोक नहीं सकते।

वैसे तो झरनों में जादुई आकर्षण होता है और वे लंबे समय से रहस्यमय आकर्षण का हिस्सा रहे हैं। उनकी ध्वनि, ऊर्जा और सुंदरता हमेशा मन मोह लेती है। चाहे आप गर्मियों में जाएं या सर्दियों में हर मौसम एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है, लेकिन मानसून की यात्रा झरनों को उनके सबसे शानदार रूप में दिखाती है। यदि आप झरनों को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यहां भारत के कुछ सबसे सुंदर झरने हैं जिन्हें आपको अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार अवश्य देखना चाहिए।

शिवानासमुद्र झरना, कर्नाटक

भारत के सबसे शानदार झरनों की सूची में सबसे ऊपर शिवनसमुद्र झरना है। कर्नाटक के मध्य जिले में स्थित इस झरने की दो अलग-अलग शाखाएं हैं- पूर्वी और पश्चिमी। हरे-भरे कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के भीतर बसा यह झरना कई तरह की विदेशी वनस्पतियों और जीवों से घिरा हुआ है।

फोटोग्राफरों को यह स्थान लुभावनी तस्वीरें खींचने के लिए एकदम सही लगेगा। भारत में दूसरा सबसे बड़ा झरना होने के कारण, शिवानासमुद्र हमेशा ही पर्यटकों को प्रभावित करने में विफल नहीं होता। यहां आने का सबसे अच्छा समय जून से अक्टूबर तक मानसून के मौसम में है, जब झरने की खूबसूरती वाकई मनमोहक होती है।

जोग वाटरफॉल, कर्नाटक

कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित जोग जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसमें चार अलग-अलग झरने हैं - राजा, रानी, रॉकेट और रोवर - जो मिलकर प्रभावशाली जोग झरने बनाते हैं। पहाड़ी इलाकों और हरे-भरे जंगलों की पृष्ठभूमि में स्थित, जोग जलप्रपात का नजारा हमेशा मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। पानी घाटी में 253 मीटर नीचे गिरता है, जिससे एक गड़गड़ाहट पैदा होती है जो बातचीत को दबा देती है। अतिरिक्त रोमांच के लिए, शानदार नजारे देखने के लिए

व्यूपॉइंट तक ट्रेकिंग करने पर विचार करें।

अथिरापल्ली झरना, केरल

केरल में अथिरापल्ली झरना देखने लायक है। त्रिशूर के वज़ाचल जंगल में चालकुडी नदी से निकलने वाला यह झरना 80 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। आस-पास के जंगल और हरियाली एक मनोरम वातावरण बनाते हैं। बेहतरीन अनुभव के लिए, जून से सितंबर के बीच मानसून के मौसम में अपनी यात्रा की योजना बनाएं, जब झरना अपने सबसे प्रभावशाली रूप में होता है।

दूधसागर झरना, गोवा

दूधसागर झरना भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक, यह चार-स्तरीय झरने के रूप में 310 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। घने जंगल से घिरा यह झरना अपने तल पर झागदार और दूधिया दिखाई देता है, जिसके कारण इसे ₹दूध का सागर₹ नाम दिया गया है।

आप जीप बुक करके या ट्रेकिंग करके झरने तक पहुंच सकते हैं। इसकी अद्भुत सुंदरता ने इसे फिल्म शूटिंग के लिए एक लोकप्रिय स्थान बना दिया है। घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जनवरी तक है।

नोहकलिकाई झरना, मेघालय

मेघालय के चेरापूंजी में नोहकलिकाई झरना देश के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। यह 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, जो एक असाधारण दृश्य प्रस्तुत करता है। प्रकृति ने इस स्थल को असाधारण सुंदरता से सजाया है। खासी भाषा में, 'नोहकलिकाई' का अर्थ है 'लिकाई की छलांग', जिसका नाम एक दुखद किंवदंती के नाम पर रखा गया है। कहानी लिकाई नाम की एक महिला के बारे में बताती है जिसने अपने बच्चे को खोने के बाद इस स्थान से छलांग लगा दी थी।

उंचली झरना, कर्नाटक

जोग झरने से कुछ ही दूरी पर स्थित उंचली झरने के साथ एक और रत्न। हालांकि यह अक्सर छाया में रहता है, लेकिन यह देखने लायक है। मानसून के दौरान, आप झरने के तल पर एक इंद्रधनुष बनते हुए देख सकते हैं - वास्तव में एक जादुई नज़ारा। झरने का असामान्य आकार और कुछ हद तक अनियमित प्रवाह एक दिलचस्प यात्रा बनाता है, खासकर जब भीड़ कहीं और व्यस्त हो।

भागसू झरना, हिमाचल प्रदेश

मैक्लॉडगंज में भागसू झरना एक छिपा हुआ खजाना है जिसे खोजा जाना चाहिए। यह शांत झरना एक शांत विश्राम प्रदान करता है, जो पर्यटक को शांति की भावना से भर देता है।

इसकी प्राकृतिक सुंदरता मनमोहक है और ऑफ-सीजन के दौरान आने से आप सामान्य भीड़ के बिना आसपास के वातावरण का आनंद ले सकते हैं। झरने की मधुर ध्वनि और पक्षियों की चहचहाहट विश्राम और कायाकल्प के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करती है।

डीयू में आरक्षित वर्ग के शिक्षक पदों को भरने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाने की फोरम की मांग -वीसी को लिखा पत्र

प्रोफेसर काले कमेटी की उपेक्षा करके हो रही है कॉलेजों में प्रिंसिपल पदों पर नियुक्ति

दिल्ली विश्वविद्यालय ने नहीं बनाया प्रिंसिपल पदों का रोस्टर।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस (शिक्षक संगठन) के चेयरमैन डॉ. हंसराज सुमन व महासचिव प्रोफेसर के.पी. सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को पत्र लिखकर मांग की है कि जिन कॉलेजों ने अपने यहाँ शिक्षक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से उन कॉलेजों के प्रिंसिपलों को एक सर्कुलर जारी कर सख्त निर्देश दिए जाए कि वे प्रिंसिपल पदों पर आरक्षण व रोस्टर रजिस्टर तैयार कर उन्हें भरे, प्रोफेसर पदों पर आरक्षण तथा शिक्षक पदों का बैकलॉग व शॉटफाल पूरा करने के लिए डीओपीटी, यूजीसी गाइडलाइंस -2006 का पालन करते हुए प्रोफेसर काले कमेटी द्वारा सुझाए गए नियमों के तहत शॉर्टफाल व बैकलॉग पदों को निकालकर इन पदों को स्पेशल ड्राइव के तहत (विशेष भर्ती अभियान) भरा जाए ताकि इन वर्गों के साथ वास्तविक रूप में सामाजिक न्याय हो सके।

फोरम के चेयरमैन डॉ. हंसराज सुमन ने कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को लिखें पत्र में बताया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में नौ साल पहले एससी/ एसटी के कल्याणार्थ संसदीय समिति , शिक्षा मंत्रालय, एससी/एसटी कमीशन, यूजीसी व डीओपीटी के अधिकारियों की टीम के साथ 9 जुलाई 2015 को दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षण की समीक्षा करने, प्रोफेसर के पदों पर आरक्षण लागू कराने और प्रिंसिपल के पदों पर आरक्षण लागू कराने का आश्वासन देकर गयी थी। साथ ही आरक्षित वर्गों के शैक्षिक व गैर शैक्षिक पदों का शॉटफाल व बैकलॉग पूरा करने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन पिछले नौ साल से संसदीय समिति की रिपोर्ट पर कोई विचार नहीं किया गया, न ही विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उस पर आगे कार्यवाही की गई। प्रोफेसर काले कमिटी की रिपोर्ट को लागू न करने के कारण दलित, पिछड़े वर्ग के शिक्षकों में गहरा रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया डीयू में प्रिंसिपल पदों के विज्ञापन निकालकर नियुक्तियाँ हो रही है लेकिन उन पदों पर संवैधानिक नियमों के तहत आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।

डॉ. सुमन ने बताया है कि संसदीय समिति जब दिल्ली विश्वविद्यालय में आई तो उसने पाया कि यहाँ प्रोफेसर के पदों पर और प्रिंसिपल के पदों पर आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। साथ ही पोस्ट बेस रोस्टर को भी यूजीसी व डीओपीटी के निर्देशानुसार

लागू नहीं किया जा रहा है। संसदीय समिति ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने बाद में प्रोफेसर के पदों पर आरक्षण दे दिया लेकिन प्रिंसिपल के पदों पर आज तक आरक्षण नहीं दिया। उनका कहना था कि विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल के पदों को क्लब करके रोस्टर रजिस्टर तैयार करना चाहिए था, उसके बाद इन पदों को रोस्टर के अनुसार आरक्षण लागू करते हुए विज्ञापित किया जाना चाहिए था। विशेष भर्ती अभियान तथा बैकलॉग के तहत एससी/एसटी, ओबीसी के अभ्यर्थियों से इन पदों को भरा जाना चाहिए था। लेकिन फोरम ने खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि पिछले नौ साल से संसदीय समिति की रिपोर्ट को आज तक दिल्ली विश्वविद्यालय ने लागू नहीं किया है, ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने आज तक प्रिंसिपल के पदों का रोस्टर ही तैयार किया है। उन्होंने प्रोफेसर काले कमेटी की रिपोर्ट को एकेडमिक काउंसिल में रखा ही नहीं। उन्होंने बताया है कि डूटा की कार्यकारिणी की हुई शनिवार को मीटिंग में डॉ. हंसराज सुमन ने प्रोफेसर काले कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने , कॉलेजों / विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा आरक्षित सीटों पर अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सूटेबल करने का मुद्दा उठाया । साथ ही उन्होंने शिक्षकों के बैकलॉग व शॉटफाल पदों को भरने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाने की मांग की है ।

फोरम के महासचिव प्रोफेसर के.पी. सिंह ने डीयू कुलपति को लिखें पत्र में बताया है कि डीयू के कॉलेजों में प्रिंसिपल के पदों पर आरक्षण देने के लिए एससी, एसटी की कल्याणार्थ संसदीय समिति 9 जुलाई 2015 तथा दिसम्बर 2020 में ओबीसी कमीशन दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी टीम के साथ आई थी। 18 दिसम्बर 2015 को समिति ने एक रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की थी, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के प्रिंसिपल पदों को क्लब करके रोस्टर रजिस्टर बनाया जाये। इस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल पदों पर आरक्षण लागू होने पर एससी-12, एसटी-06 और ओबीसी कोटे के-22 पद बनते हैं, लेकिन आज तक दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रिंसिपल पदों को क्लब करके रोस्टर रजिस्टर तक नहीं बनाया है। इस मुद्दे को विश्वविद्यालय की एकेडेमिक काउंसिल के सदस्यों ने काउंसिल की मीटिंग में कई बार उठाया है लेकिन इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह मौन है। फोरम ने कुलपति को लिखे पत्र में बताया है कि यूजीसी गाइडलाइंस-2006 के अनुसार प्रोफेसर के पदों पर आरक्षण देना अनिवार्य किया गया है। प्रोफेसर और प्रिंसिपल के पद एक ही वेतनमान के हैं तो फिर प्रिंसिपल के पदों पर आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

प्रोफेसर सिंह ने यह भी मांग की है कि जिन कॉलेज में ऑफिसिएटिंग प्रिंसिपल बने पांच साल से ज्यादा हो चुके हैं उन्हें तुरंत हटाकर क्लब किए गए रोस्टर के अनुसार प्रिंसिपलों के पदों का विज्ञापन निकाल कर नियुक्ति की जाए।उन्होंने बताया है कि दिल्ली सरकार के कॉलेजों में 15 से अधिक प्रिंसिपलों के पदों पर स्थायी नियुक्ति होनी है, इन पदों पर ऑफिसिएटिंग प्रिंसिपल लगे हुए है। प्रोफेसर सिंह ने बताया है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन प्रोफेसर काले कमेटी की रिपोर्ट को सही से लागू करता है तो प्रिंसिपल के एससी -12 एसटी -06 व ओबीसी -22 पदों पर प्रिंसिपल पदों पर नियुक्ति होगी। उनका कहना है कि पांच साल कार्यकाल पूरा कर चुके प्रिंसिपलों को हटाकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से कार्यवाहक या स्थायी प्रिंसिपलों की नियुक्ति की जाए।

डॉ. हंसराज सुमन
चेयरमैन -फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस
प्रोफेसर के.पी. सिंह
महासचिव

कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर बना बवंडर

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

नई दिल्ली । दिल्ली के निर्भया कांड की गूंज देश में थमने का नाम नहीं ले रही है। बेखौफ बलात्कारियों के हौसले दिन ब दिन बढते ही जा रहे हैं। छोटी बच्चियों से लेकर जवान और बुजुर्गो तक को नहीं बख्शा जा रहा है। हर बार की तरह सरकारी तौर पर कडे कानून बनाने से लेकर फांसी तक पर लटकाने की सख्त सजा देने की वकालत की जाती है। लेकिन बलात्कारी हर बार खाकी को ठेंगा दिखा देते है। ढर्रा फिर ज्यूं का त्यों आबाद है। मानिये जब से पुलिस ने डंडा हाथ से छोडा है तब से खाकी से खौफ ही खत्म. हो गया है।

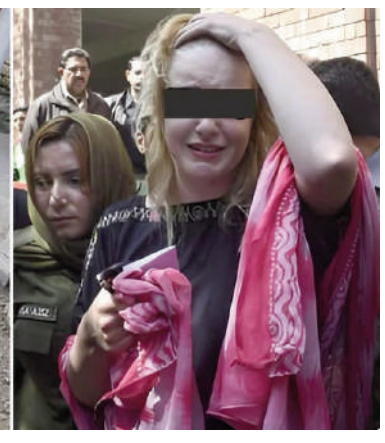

भारत में हर दिन 88 रेप की घटनाए होती है। हर घंटे 3 रेप दर्ज होते है। हद है कि वर्ष 2019 में देश में करीब 32033 मामले दर्ज किए गए। 10 साल में बलात्कार के मामलों में 31% फीसदी की बढोतरी दर्ज की गई है। कोलकाता के ताजा मामले में बलात्कारी ने निर्भय को पीछे छोड़ दिया है। यहां तो पुलिस ओर सरकारी अमला तक बलात्कारी के साथ खडा दिखाई दे रहा है। आखिर कोर्ट की चाबुक ने पूरी बंगाल सरकार की सियासत पर ही सवाल उठाते हुए मामला सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई के मैदान में आते ही इस रेप मर्डर कांड की परते उखडने लगी है।सीबीआई ने मुख्य आरोपियों की धरपकड शुरू कर दी है।। इस बीच देश के तमाम डॉक्टरों की हडताल जारी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) भी डाक्टरों की सुरक्षा को लेकर मैदान में कूद गई है। इस मामले में हद तो तब हो गई जब बंगाल सरकार ने रेप मर्डर के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले 42 प्रोफेसरों डाक्टरों का ही तबादला कर दिया। बंगाल सरकार अब बंगाल में महिला सुरक्षा के लिए‘ रात्रेर साथ ऐपर’ हेल्पलाइन नंबर जारी करने जा रही है। इससे वर्क प्लेस बनेंगे सेफ। उल्लेखनीय है कि रेप और मर्डर को लेकर जैसे जैसे कानून बनाने की वकालत की गई वैसे वैसे रेप करने वालों के हौसले बुलंद होते गए। बलात्कारियों में कानून और पुलिस का बेखौफ इस कदर है कि राह चलते हथियार के बल पर परिवार बच्चो के सामने रेप को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि सामूहिक दुष्कर्म में पडोसी देश पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। पाकिस्तान में विदेशी बेल्जियम की लडकी के साथ 6 दरिदें 5 दिनों तक लगातार बारी-बारी से रेप करते रहे । यह दरिंदगी पाकिस्तान के पॉश इलाके पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के सैक्टर-6 में, 14 अगस्त को पाकिस्तान की आजादी वाले दिन यह सब होता रहा। दरअसल बर्बरता का कोई धर्म, इमान नहीं होता, क्रूरता की कोई सीमा नहीं होती। दुनिया के देशों में महिलाओ के खिलाफ कई घटनाएं होती है, लेकिन इस मामले में शायद हमारा पडोसी देश सबसे आगे है ।पांच दिन तक 6 लोगों ने बेल्जियम की विदेशी महिला से मारपीट, दरिंदगी, के अलावा सामूहिक बलात्कार किया और फिर मन भर जाने के बाद हाथ पैर बांधकर और मुंह पर पट्टी लगाकर जंगल में फेंक दिया। आसपास के लोगो ने जब एक 28 साल की विदेशी महिला को इस हालत में देखा तो पुलिस को सूचित किया गया। दूसरे मामले में 8 जून को भी इस्लामाबाद के 6 और 4 इलाके में एक अन्य विदेशी महिला के साथ उसकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्ड ने कथित तौर पर सामूहिक गैंग रेप कर डाला। वैसे भी गैर इस्लामियों के प्रति उनका रूख काफी भयानक है। आंकडों के मुताबिक पाकिस्तान में 4 साल में करीब 22000 महिलाए गैंग रेप का शिकार बनाई गई। साल 2023 में पाकिस्तान में बलात्कार के 6624 मामले सामने आए। बता दे कि फैंसलाबाद गैंग रेप सबसे अव्वल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 और 2021 के बीच पूरे पाकिस्तान मे 21900 महिलाओ के साथ बलात्कार की सूचना मिली थी। लेकिन भारत देश रेप-मर्डर मामलों में सबसे आगे है। सरकार रेप-मर्डर के दरिंदों को कब कानून का खौफ दिखाएगी ? ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल खाकी से बेखौफ दरिंदों की आवारगी, और अपने शिकार की तलाश में सफर जारी है। दूसरी ओर डॉक्टरों की हडताल न्याय मिलने तक जारी है।

आईआईएम अहमदाबाद से ट्रेनिंग लेकर लौटा 48 एमसीडी स्कूल प्रिंसिपलों का एक और समूह

सुषमा रानी

नईदिल्ली, 18 अगस्त, दिल्ली के सरकार स्कूलों की तरह ही अब दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में भी शिक्षा क्रांति की शुरूआत हो चुकी है। इस दिशा में आईआईएम अहमदाबाद से पाँच दिवसीय ट्रेनिंग लेकर लौटे एमसीडी स्कूलों के 48 प्रिंसिपलों से शिक्षा मंत्री आतिशी व मेयर शैली ओबरॉय ने संवाद किया। इस अवसर पर प्रिंसिपलों ने आईआईएम की अपनी लीडरशीप ट्रेनिंग, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और पैरेंट्स को शिक्षा में भागीदार बनाने समेत ट्रेनिंग में सीखे हर पहलुओं से जुड़े अनुभव साझा किए।

इस मौक़े पर शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि, आईआईएम से ट्रेनिंग लेकर लौटे हमारे प्रिंसिपलों का जोश और उत्साह देखने लायक़ है। उन्होंने कहा कि जब भी सरकारी स्कूल, वहाँ के टीचर्स-प्रिंसिपल्स की बात आती है तो पूरे देश की अवधारणा है कि वो उदासीन होते है। लेकिन मुझे ख़ुशी है कि, हमारे प्रिंसिपलों ने इस अवधारणा को तोड़ने का काम किया है। हमारे प्रिंसिपल अपने जोश, उत्साह और सकारात्मकता को अपने स्कूल के टीचर्स और बच्चों में भी फैलायेंगे

शिक्षा मंत्री आतिशी ने प्रिंसिपलों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि, स्कूलों में इस देश का भविष्य पढ़ रहा है और देश के भविष्य को संवारने की ज़िम्मेदारी हमने अपने स्कूलों के शिक्षकों-प्रिंसिपलों को दी है। ऐसे में हमारे लिए शिक्षकों-प्रिंसिपलों से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कोई नहीं है।

उन्होंने कहा कि, “जिस तरह से शिक्षक-प्रिंसिपल हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम उनके लिए दुनिया की सबसे शानदार ट्रेनिंग का प्रबंध कर रहे है, ठीक उसी तरह हम चाहते है कि शिक्षक-प्रिंसिपल हमारे स्कूली बच्चों को भी शानदार शिक्षा दे। स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा ये महसूस करें कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है और वो स्कूल आकर डरे नहीं बल्कि स्पेशल महसूस करें।”

शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि, जो बच्चे सरकारी स्कूलों में आ रहे है, उन्हें उनके शिक्षकों-प्रिंसिपलों के अलावा गाइड करने, आगे बढ़ने का मौक़ा देने वाला कोई और नहीं है। यदि हम उन बच्चों को मौक़ा नहीं दे पाते तो शायद इन बच्चों को दुबारा कभी मौक़ा नहीं मिलेगा। ऐसे में सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों की ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है कि, वो जितनी सकारात्मकता के साथ इन बच्चों को मौक़ा देंगे, ये बच्चे उतने ही सफल बनेंगे। इन बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है उन्हें बस राह दिखाने की ज़रूरत है।

शिक्षा मंत्री आतिशी ने आगे कहा कि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विज़न है कि जैसी शिक्षा उन्होंने अपने बच्चों की दी वैसी शिक्षा वो दिल्ली के हर बच्चे को दे। उन्होंने कहा कि, इस विज़न को पूरा करना हमारी ज़िम्मेदारी है इसलिए हम अपने शिक्षकों को आईआईएम भेज रहे है। और हमारे लिए ख़ुशी कि बात है कि, अबतक 350 से ज़्यादा एमसीडी प्रिंसिपल विभिन्न आईआईएम से ट्रेनिंग लेकर आ चुके है। और आने वाले समय में और प्रिंसिपल ट्रेनिंग पर जाएँगे।

शैली ओबेरॉय ने कहा हमारे प्रिंसिपल ये ज़िम्मेदारी तभी बखूबी रूप से निभा पायेंगे जब वो हर चीजों को बेहतर ढंग से मैनेज कर पायेंगे। इसलिए अपने स्कूल प्रिंसिपलों के मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए हम उन्हें देश के टॉप मैनेजमेंट संस्थान आईआईएम में ट्रेनिंग के लिए भेज रहे है।

उन्होंने कहा कि, हमनें अपने प्रिंसिपलों को सबसे शानदार ट्रेनिंग दिलवाने की अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है। अब हमारे प्रिंसिपल्स एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे को शानदार शिक्षा देने की अपनी ज़िम्मेदारी निभाये।

मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि, इन ट्रेनिंग के बाद हमारे प्रिंसिपलों ने जो स्किल्स सीखे है उसका इस्तेमाल वो अपने स्कूलों को बेहतर बनाने में करेंगे और वो दिन दूर नहीं है जब एमसीडी स्कूल भी दिल्ली सरकार के स्कूलों की तरह शानदार बनेंगे और देश दुनिया में उनका नाम होगा।

वसीम रिजवी को कोलकाता पुलिस ने तलब किया “द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल” की रिलीज से पहले

सुषमा रानी

30 अगस्त 2024 को रिलीज़ होने वाली फिल्म “द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल” ने तीव्र बहस छेड़ दी है, जिसमें कोलकाता पुलिस द्वारा वसीम रिज़वी, जिन्हें जितेंद्र नारायण सिंह के नाम से भी जाना जाता है, को तलब किया जाना और भी आग में घी डालने जैसा साबित हो रहा है। यह जानकारी दिल्ली के पीवीआर प्लाजा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र सिंह ने बताया । उनके साथ इस कांफ्रेंस में आश्मिन मेहता और यजुर मारवाह भी मौजूद थे पहले से ही विवादों में घिरी यह फिल्म अपने बोल्ड कंटेंट और सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकताओं के बेबाक चित्रण के लिए काफी ध्यान आकर्षित कर रही है। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म के बारे में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र सिंह ने बताया कि कट्टरपंथियों के सोच पर आधारित इस फिल्म में हमने एक सच्ची बलात्कार घटना को दिखाया है हमने पूरी शूटिंग कोलकाता में की है और उसी तरह के घटनाओं से इस समय कोलकाता फिर जल रहा है

निर्देशक सनोय मिश्रा द्वारा निर्देशित और आश्मिन मेहता और यजुर मारवाह अभिनीत, “द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल” सिर्फ एक फिल्म नहीं है—यह क्षेत्र में गूंजने वाली सामाजिक-राजनीतिक ध्वनियों पर एक साहसिक टिप्पणी है। फिल्म के अनवरत संवाद और समाज के काले पक्षों का कच्चा चित्रण वर्तमान में बांग्लादेश और कोलकाता में हो रही अशांत परिस्थितियों के साथ गहराई से मेल खाता है, जिससे इसकी कहानी आज के समय में अत्यधिक प्रासंगिक हो जाती है।

फिल्म इन मुद्दों को उस यथार्थवाद के साथ चित्रित करती है जो भारतीय सिनेमा में दुर्लभ है, और उन कड़वी सच्चाइयों को सामने लाती है जिन्हें कई लोग नजरअंदाज करना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से, इससे आलोचनाओं की बाढ़ आ गई है, जिसमें फिल्म निर्माताओं पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने और सनसनीखेज बनाने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत करने का आरोप लगाया जा रहा है। सबसे हालिया कानूनी घटनाक्रम में कोलकाता पुलिस ने वसीम रिज़वी को मई 2023 में दर्ज एक मामले के संबंध में, भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और सिनेमा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चल रही जांच में तलब किया है।

इन कानूनी और सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, फिल्म निर्माता दृढ़ बने हुए हैं। उनका कहना है कि “द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल” उन कठोर वास्तविकताओं का प्रतिबिंब है जिनका सामना इस क्षेत्र में कई लोगों को करना पड़ता है, और इसका उद्देश्य विचारोत्तेजक और चर्चा को प्रोत्साहित करना है, न कि अशांति फैलाना। बांग्लादेश और कोलकाता दोनों में चल रहे अशांति और सामाजिक-राजनीतिक घटनाक्रम फिल्म के संदेश को और अधिक गहराई देते हैं, जिससे यह समकालीन मुद्दों का एक सटीक प्रतिबिंब बन जाती है।

जैसे-जैसे रिलीज़ की तारीख नजदीक आ रही है, फिल्म पहले ही लोगों की नज़रें खींचने और बातचीत शुरू करने में सफल हो चुकी है। चाहे इसे साहसी कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में सराहा जाए या इसके बोल्ड दृष्टिकोण के लिए निंदा की जाए, यह स्पष्ट है कि “द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल” सिनेमा से कहीं आगे तक गूंजने वाला एक संदेश है।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब फेस रिकग्निशन तकनीक से लगेगी छात्रों की हाजिरी, निदेशालय ने बताया- क्यों है जरूरी

परिवहन विशेष न्यूज

राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब विद्यार्थियों की हाजिरी फेस रिकग्निशन तकनीक के जरिए लगेगी। शिक्षा निदेशालय ने भी इस संबंध में स्कूलों में तैयारी शुरू कर दी है। इस तकनीक की पहले ऑनलाइन जांच की जाएगी। फिर इसका चुनिंदा स्कूलों में पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद ही निदेशालय से इसको हरी झंडी दी जाएगी।

नई दिल्ली । राजधानी के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की हाजिरी में सुधार के लिए अब तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय इस संबंध में स्कूलों में फेस रिकग्निशन तकनीक को स्थापित करने की योजना बना रहा है।

निदेशालय के अधिकारी के मुताबिक हाजिरी की सटीकता और दक्षता में सुधार के लिए फेस रिकग्निशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा, ताकि छात्र उपस्थिति के स्वचालन को प्राथमिकता दी जा सके। इस तकनीक की पहले ऑनलाइन जांच की जाएगी। शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि नई प्रणाली मैनुअल त्रुटियों को कम करेगी और छात्र उपस्थिति की वास्तविक समय की ट्रैकिंग सुनिश्चित करेगी।

पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर इसका परीक्षण होगा

उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों में इस प्रणाली को लागू करने से पहले, इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए कुछ चुनिंदा स्कूलों में पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर इसका परीक्षण किया जाएगा। इस तकनीक के कार्यान्वयन के लिए स्कूल को आवश्यक बुनियादी ढांचा, कंप्यूटर, कैमरा और साफ्टवेयर उपलब्ध कराए जाएंगे।

वर्तमान छात्र उपस्थिति दर 65 से 70 प्रतिशत उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा विभाग की वर्तमान छात्र उपस्थिति दर 65 से 70 प्रतिशत है, जिसमें महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि निदेशालय का जोर अब इस प्रतिशत को बढ़ाने पर है। इसके लिए स्कूलों की ओर से माता-पिता को उनके बच्चों की उपस्थिति पर मासिक अपडेट किया जाएगा ताकि उन्हें उनके बच्चे की हाजिरी के बारे में सूचना मिलती रहे।

साप्ताहिक परीक्षा शुरू करने की योजना

उन्होंने कहा कि छात्रों की हाजिरी बढ़ाने के लिए स्कूलों में मासिक या साप्ताहिक परीक्षा शुरू करने की योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रों को अधिक सहज महसूस कराने और नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए प्रेरित करने के लिए समग्र स्कूल के माहौल में सुधार करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में हाजिरी का प्रतिशत अधिक है वहां पर स्कूल स्तर पर जो प्रथाएं अपनाई जा रही है उन्हें अन्य स्कूलों में लागू किया जा सकता है।

तेज रफ्तार मर्सिडीज ने साइकिल सवार को रौंदा, युवक की मौत; आरोपी कार समेत गिरफ्तार

दिल्ली में आश्रम के पास एक 34 वर्षीय साइकिल सवार राजेश की मर्सिडीज कार से टक्कर लगने से मौत हो गई। मामले में दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए कार को जब्त कर लिया है और आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। घटना शनिवार की सुबह हुई थी। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

दक्षिणी दिल्ली। आश्रम फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार मर्सिडीज सवार ने शनिवार को एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में घायल साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस हिट एंड रन के इस मामले को 24 घंटे तक दबाती रही। आरोपित मर्सिडीज कार चालक की गिरफ्तारी के बाद रविवार को पुलिस ने मामले का खुलासा किया।

आरोपी का है पुरानी गाड़ियों का कारोबार

घटना सुबह 8:30 के करीब की है जब मर्सिडीज चालक ने ओवरटेक करने के चलते साइकिल सवार राजेश को टक्कर मार दी। मर्सिडीज से टक्कर लगने के कारण राजेश कसर डिवाइडर से टकरा गया जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मर्सिडीज चालक आरोपी नोएडा में पुरानी गाड़ियों का कारोबार करता है। फिलहाल पुलिस हिरासत में है। आश्रम फ्लाईओवर पर 17 अगस्त की सुबह करीब 8.30 बजे अज्ञात व्यक्ति को खून से लथपथ पड़ा देख मदनपुर खादर निवासी राजेंद्र कोहली ने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची। घायल की मौत हो चुकी थी और शव से करीब 150 मीटर दूर मृतक की साइकिल पड़ी थी। मृतक की पहचान 34 वर्षीय राजेश निवासी बी 261/128, गली नंबर 12, मदनपुर खादर के रूप में हुई है। मृतक माली का काम करता था।

आरोपित नोएडा से गिरफ्तार

सनलाइट कॉलीनी थाने में एफआइआर दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी की पहचान हुई। मर्सिडीज कार यूपी 16 बीएन 5555 मेसर्स एसडीएस इंफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत है।

आरोपित चालक की पहचान प्रदीप गौतम निवासी एच नंबर बी-78, सेक्टर 46, नोएडा के रूप में हुई है। कार को जब्त करते हुए आरोपित को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा

जामिया के शोधार्थी प्रखर श्रीवास्तव को मिली बड़ी सफलता, फ्रांस की प्रतिष्ठित साइंस लैब में मिली नियुक्ति

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वरिष्ठ रिसर्च फेलो प्रखर श्रीवास्तव को फ्रांस की एनेसी बिहेवियरल साइंस लैब में रिसर्च कॉन्ट्रैक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रखर भारत में ग्लोबल इंडेक्स ऑफ सोशल कनेक्शन के विकास पर काम करेंगे। जामिया विश्वविद्यालय के जनसंपर्क विभाग की ओर से भी प्रखर को बधाई के साथ मीडिया से जानकारी शेयर की गई है।

नई दिल्ली । जामिया मिल्लिया इस्लामिया के मनोविज्ञान विभाग के वरिष्ठ रिसर्च फेलो प्रखर श्रीवास्तव को फ्रांस की एनेसी बिहेवियरल साइंस लैब में रिसर्च कॉन्ट्रैक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रो. समीना बानो के मार्गदर्शन में शोध कर रहे प्रखर ग्लोबल इंडेक्स ऑफ सोशल कनेक्शन के विकास में योगदान देंगे। वह अपने परिवार के साथ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहते हैं।

डॉ. हंस रोचा इजरमैन एवं मिगुएल सिलान के नेतृत्व में इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्देश्य संस्कृतियों में सामाजिक संबंध तथा एकाकीपन को बेहतर ढंग से समझना है, जिसमें वैश्विक दृष्टिकोणों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत में इस परियोजना की शोध गतिविधियों हेतु प्रखर श्रीवास्तव जिम्मेदार होंगे।

उनके परियोजना निष्कर्षों का उपयोग व्यापक हित में होगा

इस परियोजना के निष्कर्षों का उपयोग विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) तथा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों सहित व्यापक शोध समुदाय एवं हितधारकों हेतु एक पैमाना बनाने के उद्देश्य से किया जाएगा। विश्व भर में सामाजिक जुड़ाव से संबंधित वैश्विक नीतियों तथा प्रथाओं को प्रभावित करने की क्षमता इस पहल में है।

कांग्रेस ने की थी वक्फ की भूमि पर कब्जे की शुरुआत, भाजपा भी उसी राह पर : मौलाना कल्बे जव्वाद

उलमा मौलाना कल्बे जव्वाद ने वक्फ बिल 2024 का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वक्फ की भूमि पर कब्जे की शुरुआत कांग्रेस ने की थी। अब भाजपा भी उसी की राह पर चल पड़ी है। यह बिल वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की साजिश है। वक्फ संपत्ति मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। इसे मुसलमानों ने अल्लाह की राह में दान दी है।

दक्षिणी दिल्ली । जोरबाग में रविवार को वक्फ बिल 2024 का विरोध करते हुए उलमा मौलाना कल्बे जव्वाद ने इसे केंद्र सरकार की बड़ी साजिश बताया। मौलाना ने कहा कि यह बिल वक्फ की संपत्ति पर कब्जे के लिए लाया जा रहा है। वक्फ संपत्ति मुसलमानों की संपत्ति है। इसे मुसलमानों ने अल्लाह की राह में दान दिया है। वक्फ बोर्ड इसका मालिक नहीं, बल्कि हिफाजत करने वाला एक चौकीदार है। उन्होंने कहा, “वक्फ जमीन पर कब्जे की शुरुआत कांग्रेस ने की थी। अब भाजपा भी उसी की राह पर चल पड़ी है। वक्फ की आठ लाख एकड़ जमीन बताई जा रही है, लेकिन इसमें से चौथाई भी बोर्ड के पास नहीं है। ज्यादातर जमीनों पर सरकार का कब्जा है।”

सरकार के फैसले पर टिकी घर खरीदार और किसानों की उम्मीदें, अगले महीने जारी होगी पहली किस्त

परिवहन विशेष न्यूज

सुरक्षा रियल्टी को लेकर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के आदेश पर प्रदेश सरकार जल्द फैसला ले सकती है। यमुना एक्सप्रेस-वे और लैंड फार डेवलपमेंट (एलएफडी) से प्रभावित किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे की पहली किस्त तीस सितंबर को जारी होनी है। इससे पहले यह तय हो जाएगा कि आदेश को लागू किया जाए या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी एसएलपी पर आगे बढ़ा जाए।

ग्रेटर नोएडा। सुरक्षा रियल्टी को लेकर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के आदेश पर प्रदेश सरकार जल्द फैसला ले सकती है। यमुना एक्सप्रेस-वे और लैंड फार डेवलपमेंट (एलएफडी) से प्रभावित किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे की पहली किस्त तीस सितंबर को जारी होनी है।

इससे पहले यह तय हो जाएगा कि आदेश को लागू किया जाए या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी एसएलपी पर आगे बढ़ा जाए। सरकार के इस फैसले से जेपी इंफ्राटेक की परियोजनाओं में 27 हजार से अधिक फ्लैट खरीदार और 22 हजार से अधिक किसानों की उम्मीदें टिकी हैं।

जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण कर चुकी सुरक्षा रियल्टी को लेकर एनसीएलएटी ने मई में आदेश दिया था। इसके तहत यमुना एक्सप्रेस-वे व पांच एलएफडी की जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को अतिरिक्त मुआवजा वितरण के लिए 1334.31 करोड़ रुपये सुरक्षा रियल्टी को यमुना प्राधिकरण के पक्ष में भुगतान करने हैं। प्राधिकरण ने अतिरिक्त मुआवजा वितरण के लिए 1689 करोड़ रुपये का दावा किया था।

प्राधिकरण ने एलसीएलएटी को आदेश को चुनौती देने के लिए तय समय सीमा नजदीक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट पर एसएलपी दाखिल कर दी है। लेकिन इस पर प्राधिकरण आगे तभी बढ़ेगा, जब प्रदेश सरकार यह तय करेगी कि उसे एनसीएलएटी के फैसला स्वीकार्य नहीं है। प्राधिकरण बोर्ड के निर्देश पर यह प्रकरण प्रदेश सरकार के फैसले के लिए भेजा जा चुका है।

किसानों को मुआवजा वितरण की समय सीमा नजदीक होने को देखते हुए सरकार से इस पर जल्द फैसला होने की उम्मीद है। अगर आदेश को स्वीकार कर लिया जाता है तो सुरक्षा रियल्टी यीडा को 356 करोड़ रुपये की पहली किस्त का भुगतान करेगी। प्राधिकरण अपने संसाधन से 450 करोड़ रुपये जुटाकर किसानों को 781 करोड़ रुपये अतिरिक्त मुआवजे की पहली किस्त तीस सितंबर को जारी कर देगा। अगली किस्त 31 मार्च 2025 को जारी होगी।

27452 घर खरीदार और 22886 किसानों का इंतजार होगा पूरा

एनसीएलएटी का फैसला लागू होने से जेपी इंफ्राटेक की परियोजना में 27452 घर खरीदारों का इंतजार समाप्त हो जाएगा। परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने से उन्हें अपने घर पर कब्जा मिलेगा। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेस-वे और एलएफडी की जमीन अधिग्रहण से प्रभावित 22886 किसानों को भी अतिरिक्त मुआवजा राशि मिलेगी।

यमुना एक्सप्रेस-वे व एलएफडी के लिए 1952.41 हेक्टयर जमीन हुई थी अधिग्रहीत

ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किमी लंबे यमुना एक्सप्रेस-वे के लिए पांच जिले गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा व आगरा की 1655.34 हे. जमीन अधिगृहीत की गई थी। इसके अलावा इंटरचेंज में 170.48 हे., टोल प्लाजा के लिए 70.77 हे. व फैसेलिटी के लिए 55.82 हे. जमीन अधिगृहीत की गई थी। इसके अलावा नोएडा, दनकौर, अलीगढ़ व आगरा जिले में पांच-पांच सौ हे. जमीन एलएफडी के लिए आवंटित की गई थी। जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को अभी तक 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि का वितरण नहीं हुआ है।

गुरुग्राम में प्लॉट बेचने के नाम पर व्यापारी से चार करोड़ की धोखाधड़ी, 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

गुरुग्राम में प्लॉट बेचने के नाम पर व्यापारी से चार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपितों ने व्यापारी को गांव सिकंदरपुर घोषी में नौ वर्ग गज प्लॉट के फर्जी कागज दिखाए थे। पीड़ित को जब पता चला कि आरोपितों ने दो साल पहले ही किसी दूसरे को प्लॉट बेच दिया था। इससे उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई।

गुरुग्राम। सेक्टर 15 पार्ट दो निवासी एक व्यापारी से प्लॉट बेचने के नाम पर चार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर रविवार को दस लोगों के विरुद्ध शिवाजी नगर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। इसमें कहा कि कुछ लोगों ने उसे प्लॉट बेचने के नाम पर चार करोड़ रुपये ले लिए। जबकि वह प्लॉट पहले ही किसी और को बेचा जा चुका था। सेक्टर 15 पार्ट दो निवासी मनोज कुमार लांबा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका शक्ति नगर में प्लास्टिक दाना सप्लाई करने का काम है।

उनकी फर्म जिले के कई कंपनियों को माल सप्लाई करती है। संदीप यादव और मनोज यादव की मानेसर में ऑटो पार्ट और प्लास्टिक बनाने की कंपनी है। मनोज लांबा ने कहा कि माल सप्लाई को लेकर उनकी संदीप और मनोज यादव से पिछले पांच साल से अच्छी जान-पहचान थी।

सस्ते दामों में प्लॉट देने का दिया झांसा

दोनों लोग फरवरी 2021 में उनकी फर्म में आए। कहा कि गांव सिकंदरपुर घोषी में नौ सौ वर्ग गज प्लॉट करीब साढ़े सात करोड़ रुपये में मिल रहा है। उन्होंने अपने पास पैसे न होने का हवाला देकर मनोज लांबा से सस्ते दामों में प्लॉट लेने की पेशकश की।

आरोप है कि मनोज लांबा के राजी होने पर मार्च में दोनों लोगों ने हल्का पटवारी से प्लॉट के कागज भी दिखवाए। इसके बाद मनोज लांबा ने संदीप और मनोज यादव के कहने पर कथित रूप से अर्श डेवलपर्स से प्लॉट की सात करोड़ 30 लाख रुपये में डील की।

अक्टूबर 2021 में तय हुई रजिस्ट्री की बात

मनोज यादव के कहने पर मनोज लांबा ने अप्रैल 2021 में इकरारनामा के रूप में डेढ़ करोड़ रुपये नकद और 50 लाख रुपये बैंक खाते में जमा कराए। नकदी शक्ति नगर स्थित फर्म के ऑफिस में दोनों आरोपितों को दी गई। अक्टूबर 2021 में रजिस्ट्री की बात तय हुई।

इससे पहले जून 2021 में संदीप और मनोज यादव समेत पांच लोग उनके ऑफिस में एक बार फिर आए। उन्होंने दो करोड़ और नकद रुपये मांगे। कहा कि वह जल्दी से जल्दी रजिस्ट्री करा देंगे। ये रुपये भी दे दिए गए।

प्लॉट देखने गए तो उड़े होश

मनोज लांबा ने आरोप लगाया कि जब वह अक्टूबर 2021 में सिकंदरपुर घोषी स्थित प्लॉट देखने गए तो यहां पर एसकेएन हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी प्लॉट पर निर्माण करा रही थी। पूछताछ करने पर पता चला कि यह प्लॉट एजेंसी ने 2019 में ही अर्श डेवलपर्स से खरीदा था।

धोखाधड़ी का पता चलने पर जब मनोज लांबा ने संदीप और मनोज यादव से पूछा और रुपये वापस करने के लिए कहा तो उन्होंने बदसलूकी की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दी।

नोएडा में अनियंत्रित स्कूटी बस से भिड़ी, चार युवक घायल

नोएडा के सेक्टर-62 मॉडल टाउन गोल चक्कर के पास रविवार सुबह हादसा हो गया। यहां एक अनियंत्रित स्कूटी बस से जा भिड़ी। हादसे में चार युवक घायल हो गए। नोएडा की सेक्टर 58 कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया है। जहां तीन युवकों की हालत नाजुक बताई जा रही है।

नोएडा। सेक्टर-62 मॉडल टाउन गोल चक्कर के पास रविवार सुबह एक स्कूटी सवार चार युवक रोडवेज की बस से जा भिड़े। हादसे में घायलों को इलाज के लिए पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिसमें तीन युवक की हालत नाजुक है। जबकि एक युवक की हालत गंभीर है। सेक्टर 58 कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस का कहना है कि एक रोडवेज बस (यूपी 32 एमएन 9854) में पीछे से एक स्कूटी की टक्कर हो गई। स्कूटी पर सवार गाजियाबाद के कृष्ण, नवीन, सनी और दीपक घायल हो गए। जिन्हें निजी अस्पताल भिजवाया गया है।

घायलों में तीन की हालत ठीक है। जबकि दीपक गंभीर रूप से घायल है। घायलों के सूचना दी गई है। बस व स्कूटी को मौके से हटवाया गया है। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। सीसीटीवी की मदद से मामले की जांच की जा रही है।

डीएस रोड पर जाने से बचें, रहेगा डायवर्जन

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की ओर से रविवार को 80 क्यूसेक गंगाजल परियोजना के अंतर्गत स्थापित पाइप लाइन में लीकेज होने को ठीक किया जाएगा। कारण डीएस रोड पर सेक्टर-68 ए ब्लाक, सेक्टर-70 बसई, क्लियो काउंटी के सामने रात 11 बजे से सोमवार की सुबह छह बजे तक डायवर्जन लागू रहेगा।

डीसीपी ट्रैफिक यमुना प्रसाद का कहना है कि डायवर्जन के कारण सेक्टर-66/67 से सेक्टर-122, पर्थला, किसान चौक की ओर जाने वाले वाहन डीएस ग्रुप तिराहे से बाएं टर्न कर ट्रांसपोर्ट नगर चौक सेक्टर-69 से गढ़ी गोलचक्कर, पर्थला गोलचक्कर होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे। मॉडल टाउन, सेक्टर-62 से सेक्टर-60 अंडरपास, डीएस ग्रुप तिराहा होकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ओर जाने वाले वाहन फेज-3 के सामने से यूटर्न कर सेक्टर-71 से पर्थला, सिग्नेजर ब्रिज होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे। असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें। यातायात असुविधा उत्पन्न होने पर यातायात हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते है।

ज्वेलरी शॉप में सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक से चली गोली, महिला घायल

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद में रविवार को एक बड़ी दुर्घटना होते-होते टल गई। यहां ज्वेलरी शॉप पर तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड की गन से अचानक गोली चल गई। यह गोली पास में खड़ी महिला के पैर में जा लगी। महिला को इलाज के लिए मोहन नगर के नरेंद्र मोहन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची है।

गाजियाबाद। साहिबाबाद कोतवाली क्षेत्र की शनि चौक के पास ज्वेलरी शॉप पर तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक से गोली चल गई। यह गोली वहां खड़ी एक महिला के पैर में लगी। इसमें महिला घायल हो गई।

पुलिस का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड बंदूक को चेक कर रहा था। इस दौरान गलती से गोली चल गई। महिला को मोहन नगर के नरेंद्र मोहन अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

50 वर्षीय महिला का नाम सावित्री देवी है। लाजपत नगर में पति देवेंद्र के साथ रहती हैं। सिक्योरिटी गार्ड का नाम कृष्णपाल है।

हॉस्टल से घर के लिए निकला BTech छात्र, 40 रुपये का लिया टिकट; पांच मिनट प्लेटफॉर्म पर घूमा और फिर कूद गया

बच्ची का पोस्टमॉर्टम कराने के लिए कब्र से निकाला शव, मेरठ में हत्या; गाजियाबाद में दोबारा होगा पीएम

ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत

लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र राज इंटर कॉलेज के निकट दिल्ली सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से 32 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।हादसे में युवक के कंधे पर गम्भीर चोट लगी थी। सूचना पर पहुंचे स्वजन ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया था। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस शॉप पोस्टमार्टम को भेज घटना की जांच कर रही है।

मुकेश पांचाल 32 उतरांचल कॉलोनी में परिवार के साथ रहता था। शनिवार रात वह राज इंटर कॉलेज के निकट रेलवे ट्रैक से गुजर रहा था। इसी दौरान सहारनपुर दिल्ली पैसेजर ट्रेन की चपेट आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंच स्वजन ने घायल युवक पास के अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के बाद उसे दिल्ली जीटीबी रेफर कर दिया जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार भास्कर वर्मा ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्ट मार्टम को भेज घटना की जांच में जुटी है।

मोदी की एक लाख युवाओं को राजनीति में लाने के पीछे की क्या है मंशा

संजय सक्सेना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से इस बात पर चिंता जता कर समाज को आईना दिखाने का काम किया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लाख गैर-राजनीतिक युवाओं को जन प्रतिनिधि के रूप में राजनीति में लाने का आह्वान किया।

देश की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब छात्र संगठनों, स्कूल कालेजों और विश्वविद्यालयों से युवा छात्र नेताओं की पौध नहीं तैयार होती है। आम युवा पीढ़ी की भी राजनीति में रूचि घटती जा रही है। यहां तक की देश के आगे ले जाने के लिये होने वाली समसामयिक राजनैतिक चर्चाओं से भी यह दूर रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से इस बात पर चिंता जता कर समाज को आईना दिखाने का काम किया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लाख गैर-राजनीतिक युवाओं को जन प्रतिनिधि के रूप में राजनीति में लाने का आह्वान किया। उनको लगता है कि ऐसा करने से जातिवाद और वंशवाद की राजनीति को खत्म करने में मदद मिलेगी। मोदी का यह कहना बिल्कुल सही है कि यह युवा अपनी पसंद की किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई एक ही पार्टी हो। पीएम मोदी को यह बात इस लिये कहना पड़ी क्योंकि आज का युवा राजनीति से विमुख हो रहा है। राजनीति के क्षेत्र में नये नवेले जन प्रतिनिधि आयेगें तो इससे निश्चित ही राजनीति का स्तर बढ़ेगा। वह लीक से हट कर राजनीति करेंगे।पीएम ने जो कहा है संभवता देश की भी यही इच्छा है,क्योंकि वह भी परिवारवाद और वंशवाद की रानजीति से ऊब चुका है। यह वह युवा होंगे जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होगी। उनके (युवाओं के) माता-पिता, भाई-बहन, चाचा-चाची, भतीजे कभी भी किसी भी पीढ़ी में राजनीति में नहीं रहे होंगे तो ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं की सोच भी अलग होगी। यह युवा चाहे पंचायत के लिए या फिर नगरपालिका, जिला परिषद या विधानसभा या लोकसभा के लिये चुनाव लड़े,इससे देश को ही फायदा होगा। सबसे बड़ी बात इससे जातिवाद और वंशवाद की राजनीति से छुटकारा मिलेगा।

मौजूदा दौर में बड़े-बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं का जैसा व्यवहार दिख रहा है, जिस तरह की भाषा का वह इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लगता नहीं कि यह नेता राष्ट्र के लिए सुचिंतित और परिपक्व भूमिका निभाने को तैयार हैं। चुनावी अभियान में तो भाषाई मर्यादाएं तार-तार होती होती ही रही हैं।लोकतंत्र के मंदिर में भी यही नजारा देखने को मिलता है। झूठ बोलना और जनता को बरगलाना- भड़काना तो राजनीति की एक जरूरत बन गया है। चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने वाला राजनीतिक तंत्र जिस तरह चिंतन और सोच के स्तर पर निचले पायदान पर पहुंच गये है, उसकी वजह से यह मान लेने में कोई बुराई नहीं है कि राजनीति में अब सुचिता बेईमानी हो गई है। हमारे नेता यह मानने को तैयार ही नहीं है कि सियासी संग्राम में भाषाई परिपक्वता की कमी को अनदेखा करना चाहिए, लेकिन क्या व्यापक राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर भी चलताऊ और स्तरहीन रवैया अपनाया जाना चाहिए? तमाम दलों के नेताओं का किसी घटना की निंदा या समर्थन अपनी राजनीति के हिसाब से करना या नहीं करना देश और समाज दोनों के लिये खतरनाक है। समाज के एक वर्ग के साथ अपना जुड़ाव दिखाना और दूसरे वर्ग को उपेक्षित रखना समृद्ध लोकतंत्र की निशानी नहीं है। इसका ताजा नजारा तब देखने को मिला जब बांग्लादेश में लोकतांत्रिक रूप्से चुनी गई शेख हसीना सरकार का सैन्य तख्तापलट हो गया। बांग्लादेश के घटनाक्रम के बाद विपक्षी खेमे में मोदी सरकार के खिलाफ बदजुबानी की जैसे प्रतियोगिता चल निकली। इसमें सबसे खतरनाक बयान उन नेताओं का था जो कह रहे थे कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं। इन नेताओं का इशारा मोदी सरकार के साथ भी ऐसा ही घटनाक्रम होने का संकेत दे रहा था। सबसे पहले कांग्रेस नेता

सलमान खुर्शीद का बयान आया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि 'जो बांग्लादेश में हो रहा है, वह भारत में भी हो सकता है।'

सलमान खुर्शीद न सिर्फ खानदानी नेता हैं, बल्कि विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। इसलिए यह मानने में कोई हर्ज नहीं कि उन्हें कूटनीति की समझ नहीं है। सलमान खुर्शीद के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता।इसके बाद तो ऐसे बयानों की बाढ़ ही आ गई। सलमान एक तरह से देश की मौजूदा सरकार को बदलने के लिए बांग्लादेश जैसी अराजक राह सुझा रहे थे। वह भारत के मौजूदा सरकार विरोधी मानस को संदेश दे रहे थे कि इसे भी इसी तरह हटाया जा सकता है। याद कीजिए मणिशंकर अय्यर को। वह पाकिस्तान जाकर वहां के लोगों से मोदी को सत्ता से हटाने में सहयोग की मांग कर चुके हैं। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने जो बयान दिया, वह भी राष्ट्र की सामूहिक भावना पर चोट करता है। उन्होंने कहा कि अपने तानाशाह को भी याद रखना चाहिए कि जनता ऐसे फैसला लेती है।आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने तो यहां तक कहा कि जो तानाशाही करेगा, उसे देश छोड़कर जाना होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया कि बांग्लादेश की तरह भारत की जनता भी पीएम आवास और गृहमंत्री के आवास में घुसेगी। उद्धव ठाकरे के प्रमुख सिपहसालार संजय राउत ने कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ, उससे देश के सत्ताधारी सबक लें।

फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जैसा हाल हसीना का हुआ, हर तानाशाह का यही हाल होगा। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक तो मीम बनाकर प्रधानमंत्री मोदी को व्यंग्य में समझाने लगीं कि दोस्त यानी हसीना गईं, अब आप बचकर रहो। वह भूल गईं कि शेख हसीना प्रधानमंत्री मोदी की नहीं, भारत की दोस्त रही हैं। उन्हें लंबे वक्त तक शरण उनकी पार्टी की नेता इंदिरा गांधी ने भी दी थी। यह भी न भूलें कि हाल तक शेख हसीना सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी गर्मजोशी से मिलती रहीं थीं। यह वह नेता हैं जो राजनीतिक रूप से मोदी और उनकी सरकार का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और जनता भी ऐसे नेताओं को अपना जनप्रतिनिधि चुनने से परहेज करती है।इसीलिये ऐसे तमाम नेता मीडिया या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने की साजिश रचते रहते हैं। यह नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिये संवैधानिक सस्थाओं को भी निशाने पर लेने से परहेज नहीं करते है। सबसे खतरनाक खेल यह चल रहा है कि यह लोग पहले तो सांवजिनक रूप से विवादित बयान देते हैं और जब मानहानि के किसी केस में फंसते हैं तो चुपचाप माफी मांगकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अपने देश के उद्योगपतियों को नीचा दिखाना, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा धूमिल करना,देश में अव्यवस्था फैलाने वाली विदेशी संस्थाओं के बयान और रिपोर्ट पर देश को बदनाम करना इनका एजेंडा बन गया है। यहां तक की न्यायपालिका भी इनसे नहीं बची हैं।

विपक्षी दलों का एक बड़ा धड़ा मोदी और अमित शाह को तानाशाह बताने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। साथ ही उनके खिलाफ बदजुबानी करने का भी अवसर हाथ से जाने नहीं देता। सवाल उठता है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गये किसी नेता को तानाशाह बताना सही है। फिर मंचों से खुलेआम उसकी कटु आलोचना हो, कई बार वह गाली में तब्दील हो जाये ऐसा दुनिया में अब तक तो नहीं देखा गया है कि तानाशाह की लानत-मलामत की जाए, उसे अशोभनीय भाषा से निशाना बनाया जाए,फिर भी ऐसे आरोपी खुले में घूमते रहे, लेकिन भारत में ऐसा हो रहा है। यह शर्मनाक और निंदनीय दोनों ही है। विपक्षी दलों के नेता बाबा साहब के संविधान को अपना राजनैतिक मोहरा तो बनाते हैं लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि राष्ट्र के प्रतिनिधित्व की बात करें या प्रतीक की, केंद्रीय सत्ता को ही संवैधानिक रूप से देश का प्रतिनिधि या प्रतीक माना जाता है। लिहाजा अंतरराष्ट्रीय मामलों पर केंद्र सरकार की राय को ही राष्ट्र की राय माना जाता है। कुछ समय पहले तक अंतरराष्ट्रीय और कूटनीतिक मामलों पर समूचा देश एक जैसी राय रखता था, लेकिन जब से राहुल गांधी, अखिलेश यादव,तेजस्वी यादव जैसे नेताओं ने परिवारवाद की राजनीति की बागडोर संभाली है तब से सियासत का स्तर काफी गिरा है। आम आदमी पार्टी भी इसके लिये ओवैसी जैसे नेता भी कम कसूरवार नहीं है। ऐसा नहीं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले भी विपक्ष के सुर सरकारी सुर से मिलते ही रहते थे, लेकिन कम से कम तमाम दलों के नेता इसे सार्वजनिक रूप से जाहिर करने से बचता था। कुछ मतभेद हुए भी तो उन्हें सीमाओं के अंदर ही दूर कर लिया गया, लेकिन राष्ट्र एक सुर में बोलता रहा, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब सवाल सही-गलत का नहीं विरोध के लिये विरोध करने का होता है।

खैर, सत्ता पक्ष को भी इसके लिये क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है इसके लिए किंचित दोषी सत्ता पक्ष भी है। क्योंकि अब वह विपक्ष की राय लेना ही उचित नहीं समझती है। होना तो यह चाहिए कि देश और लोकहित में राष्ट्रीय स्तर पर एक राय रखी जाए। अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान किया जाए, लेकिन अब तो जिम्मेदार लोग गालियां तक देने में संकोच नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश का मामला कोई पहला मौका नहीं है, जब सियासत की ओर से स्तरहीन बयानबाजी की गई हो। इजरायल और हमास के आतंकवादियों के बीच जंग में भी यही देखा गया था। जब कट्टपंथियों ने ही नहीं कांग्रेस जैसी राजनैतिक पार्टियों ने भी इसे फिलिस्तीन से जोड़कर मुसलमानों पर अत्याचार बताना शुरू कर दिया था। याद करें कि विनेश फोगाट को अयोग्य ठहरा दिए जाने पर कैसे बचकाने बयान दिए गए। किस राज्य के खिलाड़ियों ने मैडल जीता, किसने नहीं, इसका विवाद खड़ा किया जाता है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर सेबी पर उंगली उठाई जाती है। अपने देश के उद्योगपतियों पर हमला बोला जाता है।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV Drive the Future

महिंद्रा XUV700 दाम में हुई सस्ती; AX3 और AX5 वेरिएंट की कीमत हुई कम

परिवहन विशेष न्यूज

महिंद्रा ने अपनी मिड-साइज SUV सेगमेंट में आने वाली XUV700 के कई वेरिएंट की कीमतों में कटौती की है। इन वेरिएंट में AX5 और AX3 शामिल है। जिसमें इसके पेट्रोल और डीजल ऑप्शन दोनों शामिल है। जुलाई में कंपनी इसके AX7 और AX7 L वेरिएंट की कीमतों में कमी की थी। आइए जानते हैं कि कीमतों में कितनी कटौती हुई है।

नई दिल्ली। जुलाई 2024 में महिंद्रा XUV700 के AX7 और AX7 L की कीमत में कटौती के बाद अब अगस्त में भी AX5 और AX3 वेरिएंट की कीमतों में कटौती की गई है। इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट की कीमतों में 2.20 लाख तक की कीमत कम की गई थी। आइए जानते हैं कि इस बार कीमतों में कितनी कटौती गई है।

अगस्त 2024 में XUV700 की कीमत में कटौती

Mahindra XUV700 के AX5 डीजल AT 7S को 70,000 रुपये सस्ता तक सस्ता कर दिया गया है।

AX5 पेट्रोल MT 7S, AX5 पेट्रोल MT 7S विद ESP और AX5 डीजल MT 75

वेरिएंट कीमत में 50,000 रुपये कम किए गए हैं।

AX5 डीजल AT 5S और AX3 डीजल AT 75 की कीमतों में 20,000 रुपये कम किए गए हैं।

कटौती के बाद, महिंद्रा XUV700 अब 13.99 लाख रुपये से 26.04 लाख रुपये की रेंज में उपलब्ध है।

बिक्री बढ़ाने के लिए की कीमत में कमी

XUV700 की कीमत में कटौती करने के पीछे का उद्देश्य SUV की बिक्री में सुधार के लिए किया गया है। महिंद्रा की XUV700 पहले से ही बेस्टसेलर है और इसकी कीमत और कम होने से इसकी बिक्री में और भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। वहीं, जुलाई 2024 में इसकी बिक्री का आंकड़ा देखें तो उसके हिसाब से XUV700 ने सालाना आधार पर 25.79% की बढ़त दर्ज की है। इतना ही नहीं, जुलाई में कंपनी की कुल बिक्री में SUV ने 18% से अधिक का योगदान दिया।

मिड-साइज़ SUV सेगमेंट में सबसे पसंदीदा ऑप्शन

मिड-साइज़ SUV सेगमेंट में आने वाली XUV700 लोगों के बीच लगातार पसंदीदा ऑप्शन में से एक बनी हुई है। जुलाई में इसकी 7,769 यूनिट की बिक्री हुई, जिसके साथ यह दूसरे स्थान पर रही। इसने बाजार में 28.29% की हिस्सेदारी हासिल की। XUV700 टाटा सफारी, हैरियर, MG हेक्टर और हुंडई अल्काज़र जैसी गाड़ियों से बिक्री में काफी आगे रही।

विकासशील और विकसित बाजारों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री बढ़ाएगी टीवीएस: सीईओ

परिवहन विशेष न्यूज

टीवीएस मोटर कंपनी अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री विकासशील और विकसित बाजारों में बढ़ाने की योजना बना रही है।

देश में अच्छे मानसून को देखते हुए टीवीएस मोटर को दोपहिया वाहन बिक्री में इस साल ग्रामीण बाजार में अच्छी बढ़त मिलने की उम्मीद है।

दोपहिया वाहन निर्माता ने नए वाहन लॉन्च और प्रमुख क्षेत्रों में परिचालन को मजबूत होने के कारण इस वित्तीय वर्ष में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी आने की संभावना जताई है।

कुछ परेशानियों के चलते कंपनी को अफ्रीकी बाजार में गिरावट झेलनी पड़ी है, लेकिन इस साल इसमें सुधार की उम्मीद है।

कंपनी के निदेशक और सीईओ के. एन. राधाकृष्णन ने कहा कि भारत के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए एक प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में उभरने की क्षमता है और कंपनी इस पर पूरा ध्यान दे रही है।

उन्होंने विश्लेषकों से कहा कि कंपनी इंडोनेशिया में अपने संयंत्र से आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन) क्षेत्र के अन्य पड़ोसी बाजारों की जरूरतों को पूरा करेगी। वहां उसने पिछले साल अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस आईक्यूब की बिक्री शुरू की है।

टीवीएस मोटर कंपनी चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में कुल 52,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचे, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 39,000 वाहन था।

के. एन. राधाकृष्णन ने कहा, "हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में उभरेगा। ईवी आपूर्ति श्रृंखला और बुनियादी ढांचे में निरंतर सुधार को देखते हुए हमें विश्वास है कि हम ईवी खंड में मजबूत बने रहेंगे।"

उन्होंने कहा, 'जहां तक हमारा सवाल है, हम निश्चित रूप से अपने ईवी उत्पादों को आसियान बाजारों में निर्यात करना शुरू करेंगे और वहां पहले से ही उन्नत परीक्षण और सब कुछ किया जा रहा है।''

के. एन. राधाकृष्णन ने कहा कि कंपनी के पास ईवी के लिए एक सुनियोजित उत्पाद श्रृंखला है और वह जल्द ही उनमें से कुछ को उतारेगी।

उन्होंने कहा, 'पिछले साल, हमने टीवीएस आईक्यूब को आसियान और एशियाई बाजारों में उतारना शुरू किया था।'

के. एन. राधाकृष्णन ने कहा कि टीवीएस का इंडोनेशिया में अपना संयंत्र है और कुछ स्थानीय स्रोत भी हैं तथा आसियान एफटीए का लाभ भी कंपनी को वहां से अन्य देशों को निर्यात करने में मदद करेगा।

Maserati GT2 Stradale हुई पेश, 2.8 सेकेंड में पकड़ती है 100kmph की रफ्तार

परिवहन विशेष न्यूज

Maserati ने GT2 Stradale को ग्लोबल मार्केट में पेश किया है। इसे MC20 सुपरकार से ज्यादा पावरफुल और हार्डकोर बनाया गया है। इतना ही नहीं यह प्लग-इन हाइब्रिड Ferrari 296 GTB से ज्यादा फास्ट है। यह कार महज 2.8 सेकेंड में 0 से 100kmph की रफ्तार पकड़ लेती है। आइए आइए जानते हैं कि यह भारत में कम लॉन्च होगी।

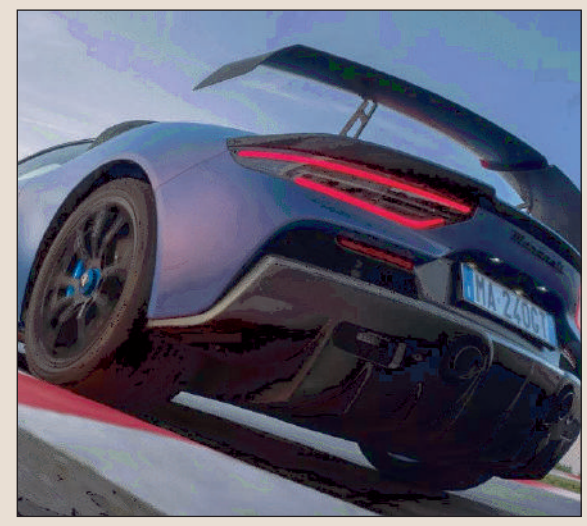

नई दिल्ली। Maserati GT2 ने अपनी MC20 सुपरकार को और भी ज्यादा हार्डकोर वर्जन को पेश किया है। इसे ट्रैक-रेडी, GT2 से बेस्ड मॉडल MC20 पर बनाया गया है और यह इससे करीब 60 किलो हल्की है। इसके 3.0-लीटर V6 टर्बो-पेट्रोल इंजन से 10hp से ज्यादा पावर मिलती है। आइए जानते हैं कि इसमें और क्या खास दिया गया है।

2.8 सेकेंड में पकड़ती है 0-100kmph की रफ्तार

मासेराटी GT2 स्ट्रैडेल में 3.0-लीटर V6 टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 640hp की पावर जनरेट करता है। कंपनी की तरफ से GT2 स्ट्रैडेल को लेकर दावा किया जा रहा है कि महज 2.8 सेकेंड में 0 से 100kph की रफ्तार पकड़ लेती है। यह 829hp वाले प्लग-इन हाइब्रिड Ferrari 296 GTB से ज्यादा फास्ट है। GT2 के बड़े रियर विंग दिए गए हैं इसे एक नए फ्रंट डिफ्यूज़र और GT2 के बड़े रियर विंग दिए गए हैं। जिससे इसके हाई स्पीड कॉर्नरिंग को बढ़ाया जा सकता है, इससे 280kph पर 500kg का एयरोडायनामिक डाउनफोर्स उत्पन्न होती है। इसके अलावा स्ट्रैडेल में GT2 के समान ही अधिक सस्पेंशन सेट-अप और स्टीयरिंग-रैक ट्यून का दिए गए हैं। मासेराटी ने इसे वेंटिलेटेड डिस्क, कैलिपर्स और पैड और थोड़ा ट्रैक-बायस्ड एंटी-लॉक सिस्टम समेत ब्रेकिंग सेट-अप दिया गया है।

कोर्सा इवो ड्राइविंग मोड से लैस

Maserati GT2 Stradale में नया कोर्सा इवो ड्राइविंग मोड दिया गया है, जो हाई फोर-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के रूप में काम करता है, लेकिन यह केवल ऑप्शन पैक के साथ उपलब्ध है। इन पैक में मिशेलिन सेमी-स्लिक टायर, एक इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड-स्लिप डिफरेंशियल, चार-पॉइंट सीटबेल्ट समेत बहुत कुछ दिया गया है।

कितनी है कीमत

मासेराटी ने अभी तक नई कार की कीमत का खुलासा नहीं किया है। कहा जा रहा है कि इस कार की कीमत 242,995 डॉलर से लेकर 522,000 डॉलर के बीच हो सकती है।

मारुति Arena की कारों को खरीदने का है विचार, तो कितना करना होगा इंतजार,

देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता Maruti Suzuki की ओर से Arena डीलरशिप के जरिए बेहतरीन फीचर्स के साथ अपनी कारों और एसयूवी को ऑफर किया जाता है। अगर आप अपने लिए कंपनी की किसी कार को खरीदने का मन बना रहे हैं तो रिपोर्ट्स के मुताबिक August 2024 में गाड़ी को घर लाने के लिए कितना इंतजार (Maruti Cars waiting Period) करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी की ओर से बाजार में हैचबैक से लेकर एसयूवी सेगमेंट तक की कारों को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कारों को August 2024 में खरीदने पर कितना इंतजार करना पड़ सकता है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

Maruti Alto K10

मारुति की ओर से Alto K10 को सबसे सस्ती कार के तौर पर ऑफर किया जाता है। अगर August 2024 में इस कार को खरीदने का मन बना रहे हैं तो इसके सभी वेरिएंट्स पर एक से दो हफ्ते का इंतजार करना पड़ सकता है।

Maruti S Presso

Arena डीलरशिप के जरिए ऑफर की जाने वाली दूसरी सस्ती गाड़ी के तौर पर S-Presso को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। इस गाड़ी के सभी वेरिएंट्स पर एक से दो हफ्ते का ही इंतजार करना पड़ सकता है।

Wagon R

मारुति की ओर से लंबे समय से हैचबैक सेगमेंट में Wagon R को ऑफर किया जाता है। कंपनी की इस गाड़ी के सभी वेरिएंट्स पर एक से दो हफ्ते का ही इंतजार करना पड़ सकता है।

Swift

मारुति ने मई 2024 में ही स्विफ्ट की नई जेनरेशन को लॉन्च किया है। इस हैचबैक कार को अगर August में खरीदने का मन बना रहे हैं तो इसके भी सभी वेरिएंट्स पर एक से दो महीने की वेटिंग चल रही है।

Dzire

कंपनी कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में Arena डीलरशिप के जरिए Dzire को ऑफर करती है। इस कार को August में खरीदने पर दो से तीन हफ्ते का इंतजार करना पड़ सकता है।

Brezza

कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मारुति एरिना डीलरशिप पर ब्रेजा को ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी को August में खरीदने पर 28 से 30 हफ्ते का इंतजार करना पड़ सकता है। यह वेटिंग इस एसयूवी के LXI CNG वर्जन पर है। इसके अलावा मैनुअल पेट्रोल के लिए एक से दो हफ्ते, CNG के अन्य वेरिएंट्स पर तीन से चार हफ्ते, पेट्रोल ऑटोमैटिक पर आठ से 10 हफ्ते की वेटिंग है।

Ertiga

मारुति अर्टिगा को भी इस महीने खरीदने पर छह से 20 हफ्ते की वेटिंग चल रही है। सबसे कम छह से आठ हफ्ते की वेटिंग पेट्रोल मैनुअल पर है। इसके सीएनजी वेरिएंट्स पर 16 से 20 हफ्ते की वेटिंग चल रही है।

Eeco

मारुति की ओर से सबसे कम कीमत वाली सात सीटों वाली कार के तौर पर Eeco को लाया जाता है।

मध्य प्रदेश की नई ईवी पॉलिसी में दोपहिया से लेकर बस खरीदी पर मिलेगी नकद सब्सिडी

परिवहन विशेष न्यूज

मध्य प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर राज्य सरकार इंसेटिव देगी। यह इंसेटिव 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर मिलेगा। इसके अलावा प्रत्येक पेट्रोल पंप पर ईवी चार्जिंग पाइंट लगाना अनिवार्य होगा। सरकारी कार्यालयों में भी चार्जिंग प्वाइंट लगाए जाएंगे। एक निर्धारित शुल्क का भुगतान कर चार्जिंग प्वाइंट का उपयोग किया जा सकेगा।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्य प्रदेश की पांच वर्षीय नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का प्रारूप तैयार कर लिया है और शासन को स्वीकृति के लिए भेजा है। इसे स्वीकृति मिलते ही इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना और सस्ता हो जाएगा।

अभी इलेक्ट्रिक वाहन पर एक प्रतिशत पंजीयन शुल्क लगता है, जिसे सरकार शून्य करने पर विचार रही है यानी अब नए इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर आरटीओ में वाहन पंजीयन शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि यह व्यवस्था एक निश्चित समय और सीमित संख्या के वाहनों के लिए ही होगी।

इसके अलावा ईवी वाहनों की पार्किंग भी फ्री करने का प्रस्ताव है। बता दें कि 2019 में बनी ईवी पालिसी को पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं। राज्य सरकार ने नई पालिसी के लिए केंद्र सरकार की पालिसी का अध्ययन कराया है और इसी के अनुरूप नई पालिसी तैयार की गई है।

इलेक्ट्रिक आटो रिक्शा के लिए शहरों में रूट तय होंगे। नगर निगम और निकाय स्तर पर इनके रूट किलोमीटर के हिसाब से तय किए जाएंगे। नई पॉलिसी के तहत शहरों में शापिंग माल और आफिस की पार्किंग में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग से पार्किंग आरक्षित की जाएगी। पार्किंग स्थान पर चार्जिंग प्वाइंट भी होंगे।

दिन में चार्ज के शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जबकि रात्रि में चार्ज करने पर बिजली का 100 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। सरकारी वाहनों की खरीद में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक साइकिल, दो पहिया, तीन पहिया व चार पहिया वाहन, बस एवं माल वाहक वाहनों के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन की व्यवस्था की जाएगी।

इन वाहनों की श्रेणियों के लिए विशेष प्रोत्साहन जैसे ऋण पर ब्याज में छूट, परमिट, पंजीयन एवं रोड टैक्स में छूट के साथ ही वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन के साथ बैट्री स्वैपिंग के लिए 25 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।

इसमें परिवहन विभाग का भी सहयोग लिया गया, ताकि क्रियान्वयन में परेशानी न आए। ईवी के लिए सिंगल विडो क्लीयरेंस स्थापित करने की भी योजना है। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निजी निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार एसओपी (स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर) बना रही है।

नई पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स से छूट देने का प्रविधान किया जा रहा है। वाहन के पंजीयन से दस साल तक टोल टैक्स से छूट दी जाएगी। शहरों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 552 ई-बसें भी खरीदी जाएगी।

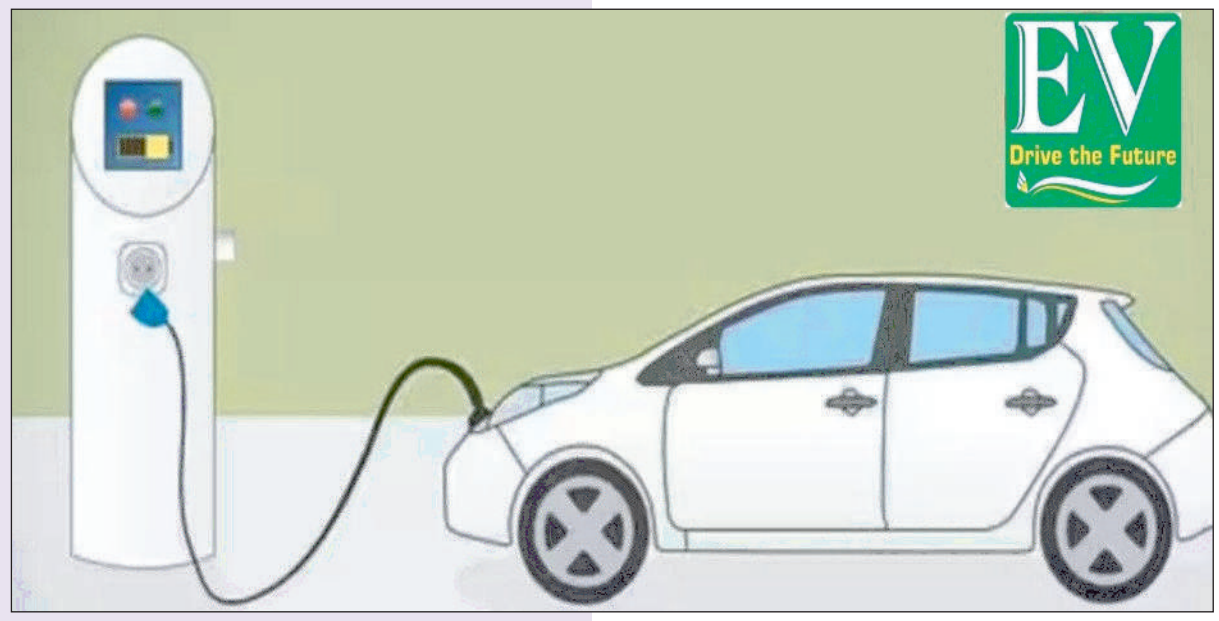

रॉयल इन्फील्ड क्लासिक 350 Bobber टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट, साल के अंत तक होगी लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बॉबर को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई क्लासिक 350 बॉबर में ऑप्शनल पिलियन सीट जुड़ी हुई दिखाई दी। इसके साथ ही दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक भी दिखाई दिए। कहा जा रहा है कि इस बाइक में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में लगे इंजन के सामन की इंजन दिया जाएगा।

नई दिल्ली। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के एक नए वेरिएंट पर कंपनी काम कर रही है। जिसका नाम बॉबर है। इस बाइक को एक बार फिर से टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। यह बाइक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 पर बेस्ड है और स्टाइल बॉबर रहने वाला है, जो कि हैंगर हैंडलबार, डीप स्कूप्ड सीट और सफेद दीवार वाले टायर की वजह से है। आइए जानते हैं कि इसमें कौन-से फीचर्स दिखाई दिए।

बाइक में जुड़ी दिखी पिलियन सीट

बॉबर स्टाइल बाइक मूल रूप से सिंगल सीट वाली बाइक है, लेकिन जो बाइक स्पॉट हुई है उसमें ऑप्शनल पिलियन सीट जुड़ी हुई है। यह बाइक की प्रैक्टिकली को बेहतर बनाने के लिए है। वहीं, रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 के साथ भी ऐसा ऑप्शन दिया जाता है।

क्लासिक 350 के जैसा होगा इंजन

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बॉबर के इंजन की बात करें तो इसमें क्लासिक 350 के समान ही देखने के लिए मिल सकता है। इसमें 349cc, एयर-कूल्ड इंजन दिया जा सकता है, जो ,100rpm पर 20.2bhp और 4,000rpm पर 27Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को पांच स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। बाइक के दोनों तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ ट्विन शॉक एब्जॉर्बर के साथ क्रैडल फ्रेम दिया गया है। दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक दिया गया है।

कई कलर ऑप्शन में होगी पेश

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बॉबर कई बेहतरीन कलर ऑप्शन के साथ पेश हो सकती है। कंपनी ने हाल ही में क्लासिक 350 के अपग्रेड मॉडल को पेश किया है और उसपर नए कलर बेहतरीन लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्लासिक 350 बॉबर को इस साल के अंत तक पेश किया जा सकता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 2 लाख रुपये होगी।

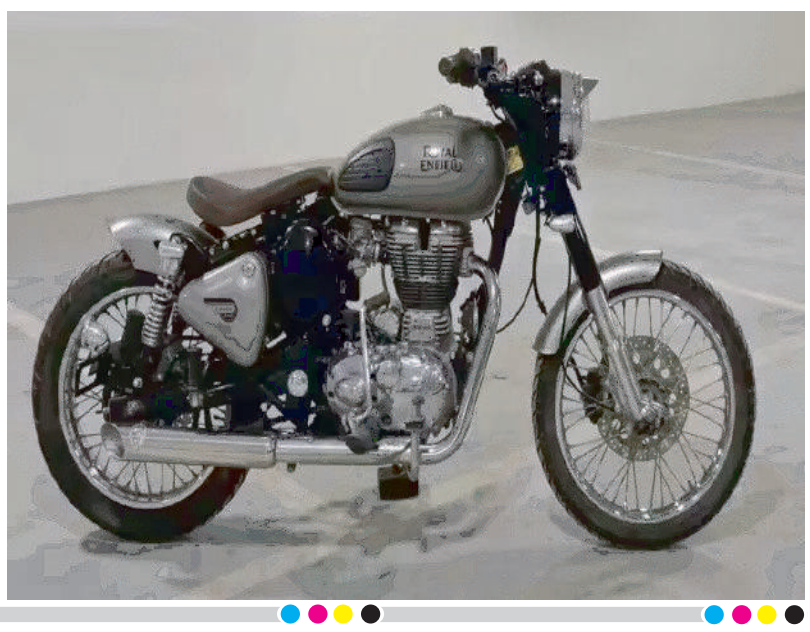

तालिबान कुशासन के 3 साल

के .एस .तोमर

अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में वापस आने के 3 साल बाद, शासन ने खुद को कई मोर्चों पर खुद को विफल साबित किया है। तालिबान के शासन में महिलाओं के खिलाफ गंभीर दमन, पड़ोसी पाकिस्तान के साथ बिगड़ते संबंध और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए निरर्थक संघर्ष...

अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में वापस आने के 3 साल बाद, शासन ने खुद को कई मोर्चों पर खुद को विफल साबित किया है। तालिबान के शासन में महिलाओं के खिलाफ गंभीर दमन, पड़ोसी पाकिस्तान के साथ बिगड़ते संबंध और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए निरर्थक संघर्ष की विशेषता रही है। जिसे कभी कुछ लोगों ने विदेशी कब्जे के खिलाफ जीत के रूप में सराहा था, वह अफगान लोगों के लिए एक दुःस्वप्न में बदल गया है। तालिबान शासन अत्याचार, महिलाओं के प्रति द्वेष और कूटनीतिक अलगाव का प्रतीक है। काबुल में तालिबान के कार्यकाल में महत्वपूर्ण चुनौतियां रही हैं, जिन्होंने उनके शासन मॉडल की सीमाओं को उजागर किया है। इन मुद्दों को संबोधित करने की उनकी क्षमता अफगानिस्तान की भविष्य की स्थिरता और सत्ता में तालिबान की दीर्घायु निर्धारित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय अलगाव, आर्थिक पतन, सुरक्षा खतरे और आंतरिक विभाजन महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, जिनसे तालिबान को आने वाले वर्षों में निपटना होगा। अगस्त 2021 से काबुल पर तालिबान के नियंत्रण को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसने उनके शासन और राजनीतिक वैधता का परीक्षण किया है। जैसे-जैसे वे सत्ता में 3 साल के करीब पहुंच रहे हैं, समूह के सामने कई प्रमुख मुद्दे सामने आ रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और अलगाव : तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा काफी हद तक मान्यता नहीं दी गई है, जो औपचारिक राजनयिक संबंधों में संलग्न होने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों तक पहुंचने की उनकी क्षमता को बाधित करता है। अफगानिस्तान विदेशी सहायता पर बहुत अधिक निर्भर है, जो तालिबान के अधिग्रहण के बाद से काफी कम हो गई है। प्रतिबंधों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है।

आर्थिक पतन : अफगान अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, मुद्रा का मूल्यह्रास हो रहा है और मुद्रास्फीति बढ़ रही है। बैंकिंग प्रणाली पतन के कगार पर है और देश को नकदी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापक बेरोजगारी और गरीबी बदतर हो गई है, जिससे मानवीय संकट पैदा हो गया है। कई अफगान बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं और खाद्य असुरक्षा व्याप्त है।

सुरक्षा और आंतरिक संघर्ष : इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आई.एस.एस.-के) लगातार खतरा बना हुआ है, जो पूरे अफगानिस्तान में घातक हमले कर रहा है। इन हमलों के जारी रहने से तालिबान की सुरक्षा बनाए रखने की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। तालिबान के भीतर आंतरिक विभाजन हैं, जिसमें अलग-अलग गुट सत्ता के लिए होड़ कर रहे हैं। ये विभाजन संभावित रूप से अंदरूनी कलह का कारण बन सकते हैं और उनके नियंत्रण को अस्थिर कर सकते हैं।

नारकोटिक्स और अवैध अर्थव्यवस्था : अफगानिस्तान अफीम का एक प्रमुख उत्पादक है, और तालिबान पर नशीली दवाओं के व्यापार से मुनाफा कमाने का आरोप लगाया गया है। इसने न केवल उनके संचालन को वित्तपोषित किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जांच और प्रतिबंधों को भी आकर्षित किया है। जबकि तालिबान ने अफीम उत्पादन पर अंकुश लगाने की कसम खाई है, ये प्रयास असंगत रहे हैं और अवैध अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है।

मानवीय संकट : अफगानिस्तान दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रहा है, जहां लाखों लोग भूख और ढहती स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का सामना कर रहे हैं। तालिबान बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहा है और इन मुद्दों को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों पर निर्भर है। महिला विरोधी शासन : तालिबान शासन के तहत, अफगान महिलाओं को उनके अधिकारों और स्वतंत्रताओं का विनाशकारी नुकसान उठाना पड़ा है। शासन ने पिछले 2 दशकों में की गई प्रगति को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया है, शरिया कानून वापस लौट आया है जो महिलाओं के बुनियादी मानवाधिकारों को छीन लेता है। शिक्षा, जो अफगान महिलाओं के सशक्तिकरण के स्तंभों में से एक है, को बेरहमी से निशाना बनाया गया है। लड़कियों और महिलाओं को माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे वे प्रभावी रूप से शैक्षणिक क्षेत्र से गायब हो गई हैं।

भारत का तालिबान के साथ संबंध : भारत का तालिबान के साथ संबंध जटिल और सतर्क है। भारत ने ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकारों का समर्थन किया है और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के साथ तालिबान के संबंधों को लेकर चिंतित है। हालांकि नई दिल्ली ने सावधानीपूर्वक तालिबान के साथ संवाद के चैनल खोले हैं जिसमें अफगान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश सहित अपने हितों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित करने की इच्छा से प्रेरित होकर भारत की भागीदारी सीमित बनी हुई है।

पाकिस्तान के साथ दुश्मनी : कभी करीबी सहयोगी और समर्थक के रूप में देखे जाने वाले पाकिस्तान के साथ तालिबान के संबंध पिछले 3 वर्षों में काफी खराब हो गए हैं। पाकिस्तान, जिसने तालिबान को उसके विद्रोह के दौरान शरण और समर्थन प्रदान किया था, अब खुद को उस शासन के साथ असहमत पाता है जिसे उसने स्थापित करने में मदद की थी। चीन ने मुख्य रूप से सुरक्षा चिंताओं और आर्थिक हितों से प्रेरित होकर तालिबान के साथ सावधानीपूर्वक जुड़ाव बनाए रखा है। दुनिया देख रही है कि तालिबान के शासन में अफगानिस्तान अराजकता और निराशा में डूब रहा है और बेहतर भविष्य की कोई उम्मीद नहीं है।

संपादक की कलम से

मेरा भारत महान, जुग-जुग जीवे हिन्दुस्तान'

'हर बाधा को पार कर आगे बढ़ते जाएंगे'

15 अगस्त के दिन भारत ने अपनी स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ मनाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 11वीं बार लालकिले पर तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस पर सर्वाधिक 17 बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकार्ड पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम है और उनके बाद इंदिरा गांधी ने 16 बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। देश की स्वतंत्रता के समय हमारी जनसंख्या 34.20 करोड़ के लगभग थी जो अब 140 करोड़ हो गई है और अब तक के सफर के दौरान हमने विकास के अनेक पड़ाव तय किए हैं। देश के ओर-छोर में रेल, बस और विमान सेवाओं का जाल फैलता जा रहा है। बदल-बदल कर सरकारें आ रही हैं।

स्वतंत्रता के समय खाद्यान्न संकट से जूझ रहा हमारा देश आज दूसरे देशों को खाद्यान्न निर्यात कर रहा है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। अंतरिक्ष अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि सभी क्षेत्रों में देश सफलता प्राप्त कर रहा है। कोरोना काल में विश्व को वैक्सीन सप्लाई करने के कारण भारत को 'विश्व की फार्मेसी' कहा जाने लगा है। बड़ी संख्या में भारतीयों ने विदेशों में उपलब्धियां प्राप्त की हैं और अमरीका, इंगलैंड तथा कनाडा सहित अनेक देशों में भारतीय उच्च पदों पर आसीन होकर अपनी मातृभूमि का गौरव बढ़ा रहे हैं। उच्चशिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लोगों में खुशहाली बढ़ी है। वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है तथा कहीं-कहीं सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगने लगे हैं। इन सब उपलब्धियों के बावजूद देश को अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। देश में शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी का आंकड़ा जो वर्ष 2000 में 35.2 प्रतिशत था वह 2022 में बढ़ कर 65.7 प्रतिशत हो गया। सड़क, रेल और विमान परिवहन बढ़ने के साथ-साथ सड़क और रेल दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। देश में पिछले लगभग 15 महीनों में रेल दुर्घटनाओं में 300 से अधिक यात्रियों के प्राण जा चुके हैं, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में भी मौतें हो रही हैं।

देश में अपराध बढ़े हैं तथा बच्चियों और महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं। खुदरा महंगाई दर में भी वृद्धि हुई है और खाने-पीने की चीजें महंगी होने के कारण लोगों की रसोई का बजट बढ़ गया है। इन सब बातों के लिए कुछ विशेषज्ञ देश की बढ़ी हुई जनसंख्या को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। देश में आंतरिक तथा बाहरी खतरे बढ़ रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों के विरुद्ध 'आप्रेशन आलआऊट' जारी रहने के बावजूद वहां हिंसा जारी है। आतंकवादियों की सहायता करने के आरोप में उनके स्थानीय मददगार पकड़े जा रहे हैं। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। सुदूर उत्तर-पूर्व के मणिपुर में भी गत वर्ष 3 मई से जारी जातीय हिंसा थमने में नहीं आ रही है और वहां अब तक 225 से अधिक लोगों की मौत व 65,000 से अधिक लोग बेघर हुए हैं। जहां तक पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों का प्रश्न है, इनमें से पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और चीन के साथ हमारे सम्बन्ध पहले ही खराब चल रहे थे और ले-देकर बस एक बंगलादेश ही बचा था, परन्तु अब वहां भी हालात बदल रहे हैं।

वहां प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के साथ हमारे दोस्ताना सम्बन्ध थे, परंतु वहां 5 अगस्त को हुए तख्तापलट के बाद चीन समर्थक मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद स्थिति बदल गई है। तख्तापलट होते ही वहां हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों तथा उनके धर्मस्थलों को नष्ट करने की घटनाएं बढ़ गई हैं। शिक्षा संस्थानों तथा होस्टलों से हिन्दुओं तथा अन्य अल्पसंख्यकों को बाहर निकाला जा रहा है। इस तरह के हालात के बीच अपने पाठकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए हम आशा करते हैं कि अतीत की भांति ही भविष्य में भी हम अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार करके आगे बढ़ते जाएंगे और हर भारत वासी की जुबान पर एक ही नारा होगा : 'मेरा भारत महान', 'जुग-जुग जीवे हिन्दुस्तान'।

राय

'बंगलादेशी हिन्दुओं को भारत में शरण' 'भाजपा में उठने लगी आवाजें'

गत 5 अगस्त को शेख हसीना के बंगलादेश से भाग कर भारत आने के बाद से वहां हालात बेकाबू बने हुए हैं तथा देश का घटनाक्रम बता रहा है कि वहां स्थिति कितनी गम्भीर है।

गत 5 अगस्त को शेख हसीना के बंगलादेश से भाग कर भारत आने के बाद से वहां हालात बेकाबू बने हुए हैं तथा देश का घटनाक्रम बता रहा है कि वहां स्थिति कितनी गम्भीर है। यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि बंगलादेश की हिंसा में हिन्दुओं पर हमले की 200 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं जिनमें अनेक लोगों को प्राण गंवाने पड़े हैं तथा अंतरिम सरकार के प्रधान मोहम्मद यूनुस अल्पसंख्यक समुदाय को विश्वास में लेने के लिए हिंदू धर्मस्थलों में जाने के अलावा अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। इस तरह के हालात के बीच भारत सरकार द्वारा बंगलादेश के साथ लगती भू-सीमा को खोलने तथा बंगलादेशी हिन्दुओं को भारत में शरण देने के मामले में 2 प्रमुख भाजपा समर्थकों 'टी. मोहन दास पाई' तथा 'सुशील पंडित' ने सरकार से पूछा है कि पिछले एक सप्ताह से बंगलादेश में हिन्दुओं पर लगातार बढ़ रहे अत्याचारों के प्रमाण सामने आने के बावजूद हिन्दुओं को भारत आने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है?

उल्लेखनीय है कि 9 अगस्त को बी.एस.एफ. ने 1700 बंगलादेशी हिन्दुओं के भारत में दाखिल होने के प्रयास को नाकाम कर दिया था। एक प्रभावशाली राइटविंग एक्टिविस्ट 'सुशील पंडित' ने इस संबंध में कहा है कि ''बंगलादेशी ड्रूषहदुओं के प्रति सरकार की सहानुभूति का अभाव परेशान करने वाला है। हम इस बात को लेकर सरकार से परेशान हैं कि बंगलादेश में खुलेआम नरसंहार हो रहा है।'' ''केंद्र सरकार ने विलंब से वास्तविकता को महसूस करने और जुबानी जमा खर्च करने के अलावा कुछ नहीं किया, जो उचित नहीं।'' 'टी. मोहनदास पाई' के अनुसार ''अफगानिस्तान के संकट के समय सरकार ने उचित रूप से सिखों को शरण दी थी परंतु अब बंगलादेश के हिन्दुओं के साथ भारत सरकार भेदभाव क्यों कर रही है? अतीत में भारत सरकार यहूदियों तथा पारसियों तक को शरण दे चुकी है।'' दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलादेश की अंतरिम सरकार के प्रधान मोहम्मद यूनुस को बधाई संदेश देते हुए उनके नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को इस बात के लिए प्रभावित करने की कोशिश की है कि बंगलादेश में हिन्दुओं तथा अन्य अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने की जरूरत है। इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भाजपा के सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर स्वीकार किया है कि बंगलादेश का संकट भारत सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती है जिसे सुलझाना आसान नहीं। बताया जाता है कि असम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री सीमाएं खोलने के पक्ष में नहीं हैं। पिछले एक सप्ताह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इस जटिल समस्या पर भारत सरकार से चर्चा कर रहे हैं तथा विश्व हिन्दू परिषद के एक शिष्टमंडल ने गत सप्ताह गृह मंत्री अमित शाह से भेंट करके उन्हें बंगलादेशी हिन्दुओं तथा अन्य अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग भी की है। विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने आशा व्यक्त की है कि बंगलादेश सरकार हिन्दुओं पर अत्याचारों के लिए जिम्मेदार तत्वों पर काबू पाने के लिए उचित कदम उठाएगी। 'टी. मोहन दास पाई' ने उत्पीडऩ के शिकार बंगलादेशी हिन्दुओं, बौद्धों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को शरण देने की खातिर संविधान में संशोधन के लिए तत्काल अध्यादेश लाने की मांग की है। इस समय सिटीजनशिप अमैंडमैंट एक्ट (सी.ए.ए.) के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2014 से पहले मुस्लिम बहुसंख्यक पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान से आए हिन्दुओं, सिखों, बौद्धों, ईसाइयों और पारसियों को नागरिकता प्रदान की जाती है।

'भारत-अमरीका रक्षा सांझेदारी : 21वीं सदी का नया शक्ति समीकरण'

21वीं सदी में अमरीका और भारत के बीच संबंध सबसे रणनीतिक और महत्वपूर्ण संबंधों में से एक हैं। अमरीका भारत को एक अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने और एक महत्वपूर्ण सांझेदार के रूप में समर्थन करता है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और...

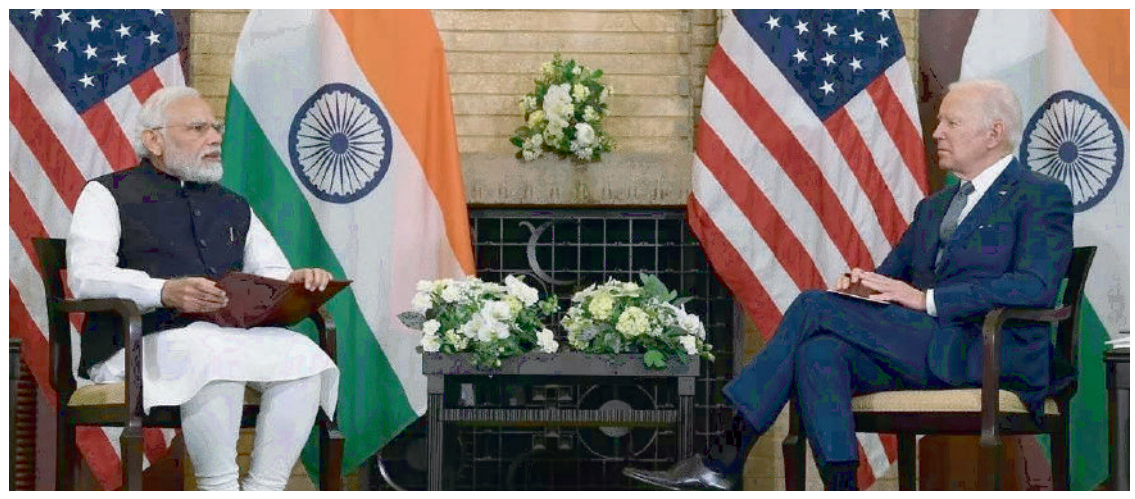

21वीं सदी में अमरीका और भारत के बीच संबंध सबसे रणनीतिक और महत्वपूर्ण संबंधों में से एक हैं। अमरीका भारत को एक अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने और एक महत्वपूर्ण सांझेदार के रूप में समर्थन करता है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में सहायक है। अमरीका और भारत ने एक मजबूत रक्षा औद्योगिक सहयोग स्थापित किया है, जो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताओं के सह-विकास और सह-उत्पादन के अवसरों की ओर देखता है। इसके साथ ही, भारत और अमरीका संयुक्त राष्ट्र, जी-20, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान)-संबंधित फोरम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय संगठनों और मंचों में घनिष्ठ सहयोग करते हैं।

भारत के आसपास का भू-राजनीतिक परिदृश्य तेजी से तनावपूर्ण होता जा रहा है। चीन का अपने पड़ोसियों जिनमें भारत भी शामिल है, के प्रति आक्रामक और आक्रामक रवैया क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा रहा है। इसके साथ ही, पाकिस्तान भी भारत के लिए एक स्थायी चुनौती बना हुआ है। चीन और पाकिस्तान के साथ दो-फ्रंट संघर्ष के खतरे का मतलब है कि भारत को सैन्य और आर्थिक रूप से तैयार रहना होगा। हालांकि, भारत का सैन्य आधुनिकीकरण धीमा रहा है और पुरानी हथियार प्रणाली अभी भी उसकी सशस्त्र सेनाओं की मुख्य धारा का हिस्सा हैं। आत्मनिर्भर पहल, जिसका उद्देश्य आत्म-निर्भरता प्राप्त करना है, को प्रभावी होने में समय लगेगा। इसके अतिरिक्त रूस के साथ जारी युद्ध और संबंधित आपूर्ति में कमी के कारण भारत रूस पर महत्वपूर्ण सैन्य हार्डवेयर के लिए निर्भर नहीं हो सकता। रूस पर अमरीकी प्रतिबंध इस समस्या को और जटिल बना देते हैं। इसलिए भारत अपने फाइटर और बख्तरबंद बेड़े को फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों की मदद से उन्नत करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि, आधुनिक सैन्य उपकरणों में महत्वपूर्ण अंतर को दूर करने के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा।

भारतीय वायुसेना वर्तमान में केवल 31 लड़ाकू स्क्वाड्रन के साथ काम कर रही है, जबकि स्वीकृत क्षमता 42 स्क्वाड्रन की है। अनुमान है कि 2030 के मध्य तक यह संख्या केवल 35-36 स्क्वाड्रन तक ही पहुंच पाएगी। अगर इस बीच कोई संघर्ष उत्पन्न होता है, तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा सकता है। इस स्थिति में, भारत की सैन्य क्षमताओं को सुदृढ़ करने में अमरीका एक महत्वपूर्ण सांझेदार के रूप में उभरता है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने अमरीका के साथ कई अरब डॉलर के रक्षा समझौते किए हैं, जो रणनीतिक संबंधों की गहराई को दर्शाते हैं। पिछले 15 वर्षों में अमरीका से भारत को आपूर्ति किए गए प्रमुख रक्षा उपकरणों में सी-130 जे सुपर हरक्यूलिस, सी-17 ग्लोबमास्टर III और पी-8इ पोसाइडन जैसे परिवहन और समुद्री विमान सी.एच. -47एफ चिनूक, एम.एच.-60 आर सीहॉक और ए.एच. -64 ई अपाचे जैसे हैलीकॉप्टर; हार्पून एंटी-शिप मिसाइलें और एम 777 हॉवित्जर शामिल हैं। नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित दो दिवसीय 'यू.एस.-इंडिया डिफैंस न्यूज कॉन्क्लेवः स्टोरीज ऑफ यू.एस.-इंडिया डिफैंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप' में अमरीका के भारत में राजदूत एरिक गार्सेटी ने यू.एस.-भारत रक्षा सांझेदारी की संभावनाओं को रेखांकित किया।

उन्होंने भारत को एक ऐसा केंद्र बनाने में रुचि व्यक्त की जहां अमरीकी जहाजों की मरम्मत हो सके, गुणवत्तापूर्ण नौकरियों का सृजन हो सके, और आपसी सिस्टम और प्रशिक्षण को बेहतर ढंग से समझा जा सके। अतः अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है और वह अपनी वर्तमान स्थिति

भारतीय महिलाओं के लिए न्याय की राह में बाधाएं

लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर अपने 98 मिनट के भाषण में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'विकसित भारत 2047' विजन के तहत महिलाओं की उन्नति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को मुख्य विषय के रूप में...

लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर अपने 98 मिनट के भाषण में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'विकसित भारत 2047' विजन के तहत महिलाओं की उन्नति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को मुख्य विषय के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों की त्वरित जांच और कठोर दंड का आह्वान किया, ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सामाजिक बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया।

मोदी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अपनी सरकार की पहलों पर भी प्रकाश डाला जिसमें स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की वृद्धि, वित्तीय स्वतंत्रता में वृद्धि, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में अधिक प्रतिनिधित्व शामिल है। उन्होंने मातृत्व अवकाश को 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने जैसे नीतिगत बदलावों का उल्लेख किया और महिलाओं के लिए अधिक न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए समान नागरिक संहिता की वकालत की। जबकि हमें भारत की विविध संस्कृति और बढ़ती अर्थव्यवस्था पर गर्व होना चाहिए, हम महिलाओं के खिलाफ हिंसा के व्यापक मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अकेले 2022 में, भारत में महिलाओं के खिलाफ 445,000 से अधिक अपराध दर्ज किए गए, जिनमें बलात्कार और घरेलू हिंसा शामिल हैं और कई और शायद रिपोर्ट ही नहीं किए गए। 1972 में मथुरा केस और 2012 में निर्भया केस जैसे हाई-प्रोफाइल मामलों ने विधायी सुधारों को जन्म दिया है, फिर भी भारतीय महिलाओं के लिए न्याय की राह में महत्वपूर्ण बाधाएं बनी हुई हैं।

आइए इस महीने की शुरूआत में 31 वर्षीय पोस्ट-ग्रैजुएट ट्रेनी डाक्टर का मामला लेते हैं, जिसकी हत्या आर.जी. कर मैडीकल कॉलेज के एक सैमीनार हॉल में की गई थी, जहां वह नाइट ड्यूटी पर थी। उसका शव अर्धनग्न अवस्था में बलात्कार और गला घोंटने के निशानों के साथ मिला, जिस पर गंभीर चोटें थीं। पास में, उसके कपड़े और बालों के साथ खून से लथपथ गद्दा मिला। कुछ पुलिस सूत्रों का अनुमान है कि बलात्कार से पहले उसकी हत्या की गई होगी। संदिग्ध संजय रॉय को अपराध स्थल पर उसका ब्लूटूथ हैडफोन मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया और उसके घर से खून से सना जूता बरामद किया गया। कोलकाता पुलिस में नागरिक स्वयंसेवक के रूप में कार्यरत रॉय का दुव्र्यवहार और धोखाधड़ी का इतिहास रहा है। हत्या के बाद डाक्टरों और चिकित्सा समुदाय ने विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जो सी.सी.टी.वी. कवरेज की कमी, डाक्टरों के लिए अपर्याप्त विश्राम क्षेत्र और रात में बाहरी लोगों की जांच नहीं होने का हवाला देते हुए अस्पताल में बेहतर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा और विपक्षी दलों पर राजनीतिक लाभ के लिए मामले का फायदा उठाने का आरोप लगाया है। बनर्जी ने दावा किया कि इन दलों ने बंगाल को बदनाम करने के लिए अभियान चलाते हुए सोशल मीडिया लाइक और मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस घटना का इस्तेमाल किया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की, जिन्होंने उनकी सरकार पर आरोपियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था, उन्होंने अन्य राज्यों में इसी तरह की घटनाओं से निपटने के कांग्रेस के तरीके पर सवाल उठाया। बनर्जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी सरकार बंगाल के खिलाफ बदनामी बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन वह आरोपियों के लिए मृत्युदंड का समर्थन करती है। कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा जांच को सी.बी.आई. को सौंपने के फैसले के बाद, उन्होंने रविवार तक अपराधी को फांसी देने का आह्वान किया।

फरवरी 2015 में, तुर्की में 20 वर्षीय विश्वविद्यालय की छात्रा ओजगेकन असलान की हत्या ने महिलाओं के खिलाफ ड्रूषहसा और सरकार की अपर्याप्त प्रतिक्रिया के खिलाफ व्यापक आक्रोश और राष्ट्रव्यापी विरोध को जन्म दिया। असलान के मामले ने उसकी हत्या की क्रूरता के कारण अभूतपूर्व ध्यान आकर्षित किया था। इस बढ़ते ध्यान का एक और कारण यह था कि मीडिया ने अपराध की चरम हिंसा को असलान की उच्च नैतिक चरित्र और विनम्रता की छवि के साथ कैसे तुलना की। उसे एक सदाचारी और विनम्र छात्रा के रूप में चित्रित किया गया था, उसका एकमात्र 'दोष' यह था कि वह स्कूल के बाद एक मिनी बस में अकेली थी, जो शॉपिंग मॉल जा रही थी। भारत में, लैंगिक-आधारित हिंसा का अक्सर राजनीतिकरण किया जाता है, और पीड़ितों को न्याय के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ सकता है। राजनेताओं के सांस्कृतिक दृष्टिकोण और खारिज करने वाली टिप्पणियां समस्या को बनाए रखती हैं और अक्सर महिलाओं पर दोष मढ़ती हैं।

महिलाओं को बिना किसी डर के जीने का हक है और इस मौलिक मानव अधिकार को बनाए रखने के लिए भारत में और अधिक काम करने की जरूरत है। सरकार को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी को निर्णायक कार्रवाई के साथ नेतृत्व करना चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूर्ण-प्रमाणित कदम सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों को शामिल करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि महिलाएं हमारे समाज का मूल हैं और हमें उनके सम्मान और सुरक्षा की रक्षा करनी चाहिए। यह हमारी परंपरा है और हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

-हरि जयसिंह

इस हफ्ते कैसा रहेगा शेयर मार्केट का मिजाज, किन फैक्टर से तय होगी बाजार की चाल?

परिवहन विशेष न्यूज

इस हफ्ते अमेरिका में सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की मीटिंग का ब्यौरा जारी होने वाला है। इससे संकेत मिलेगा कि फेडरल रिजर्व का कब से ब्याज दरें कम करने का प्लान है। अमेरिका में मंदी की आशंका भी नरम पड़ चुकी है तो दुनिया भर के शेयर बाजारों का माहौल सकारात्मक रहने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। अमेरिका में मंदी की आशंका कम होने से पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में भारी उछाल दिखा। इससे निवेशकों ने राहत की सांस ली, क्योंकि पिछले दो हफ्ते से मार्केट में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा था। आइए जानते हैं कि इस हफ्ते शेयर बाजार का मिजाज किन फैक्टर के आधार पर तय होगा।

अमेरिका से 'अच्छी खबर' का इंतजार

इस हफ्ते अमेरिका में सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की मीटिंग का ब्यौरा जारी होने वाला है। इससे संकेत मिलेगा कि फेडरल रिजर्व का कब से ब्याज दरें कम करने का प्लान है। माना जा रहा है कि यूएस फेड अगले महीने से कटौती की शुरुआत कर सकता है। अमेरिका में मंदी की आशंका भी नरम पड़ चुकी है, तो दुनियाभर के शेयर बाजारों का माहौल सकारात्मक रहने की उम्मीद है।

विदेशी निवेशकों पर भी रहेगी नजर

इस महीने की शुरुआत से ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारी बिकवाली कर रहे हैं। वे अब तक 21 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयर बेच चुके हैं। अगर इस हफ्ते भी यह ट्रेंड बरकरार रहेगा, तो मार्केट पर कुछ दबाव पड़ सकता है। इस हफ्ते सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के पीएमआई आंकड़े भी आएंगे। वहीं, 7 नए आईपीओ आने वाले हैं और 5 की लिस्टिंग होगी। इन पर भी निवेशकों की नजर रहेगी।

सात कंपनियों का मार्केट कैप बढ़ा

पिछले हफ्ते बीएसई में सूचीबद्ध शीर्ष-10 में से सात कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 1.40 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के शेयरों में सबसे ज्यादा 67,477.33 करोड़ रुपये की वृद्धि रही है। अब टीसीएस की बाजार हैसियत 15.97 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

इसके अलावा, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्री और हिंदुस्तान यूनीलिवर के पूंजीकरण में भी बढ़ोतरी रही है। दूसरी ओर, एलआईसी, एचडीएफसी बैंक और एसबीआइ का पूंजीकरण घटा है। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है।

ऑनलाइन फजीहत के बाद Cognizant की सफाई, इंजीनियरिंग फ्रेशर्स को 12 लाख तक का पैकेज देने का किया दावा

आईटी फर्म Cognizant का कहना है कि वह इंजीनियरिंग फ्रेशर्स को 4 से 12 लाख रुपये तक की एनुअल सैलरी ऑफर करती है। सोशल मीडिया पर जो 2.52 लाख रुपये का शुरुआती सालाना पैकेज बताया जा रहा है वह नॉन-इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स के लिए है। कॉग्निजेंट सालाना इंक्रीमेंट के मुद्दे पर भी तीखी आलोचना का शिकार हुई है। उसने एंप्लॉयीज को 1 फीसदी का भी इंक्रीमेंट दिया है।

नई दिल्ली। पिछले दिनों अमेरिकी आईटी फर्म कॉग्निजेंट को सोशल मीडिया यूजर्स ने काफी ट्रोल किया था। कंपनी पर आरोप था कि वह इंजीनियरिंग फ्रेशर्स को 2.52 लाख रुपये का सालाना पैकेज ऑफर करती है, जो आज की महंगाई के हिसाब से बेहद कम है। अब कंपनी सोशल मीडिया आलोचना पर सफाई दी है।

Cognizant ने सफाई में क्या कहा?

आईटी फर्म Cognizant का कहना है कि वह इंजीनियरिंग फ्रेशर्स को 4 से 12 लाख रुपये तक की एनुअल सैलरी ऑफर करती है। सोशल मीडिया पर जो 2.52 लाख रुपये का शुरुआती सालाना पैकेज बताया जा रहा है, वह नॉन-इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स के लिए है।

हमने थ्री-ईयर अंडरग्रेजुएट डिग्री के साथ नॉन-इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाली नौकरी के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। उसे गलत तरीके से पेश किया गया है। हमारी यह 2.52 लाख रुपये सालाना पैकेज वाली यह नौकरी सिर्फ 3 साल की अंडरग्रेजुएट डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए थी, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए नहीं।

कॉग्निजेंट, अमेरिकी आईटी फर्म

कॉग्निजेंट अमेरिका के EVP और प्रेसिडेंट सूर्या गुम्मादी ने कहा, ₹हम नए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए 4 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक का सालाना पैकेज ऑफर करते हैं। ह हायरिंग की कैटेगरी, स्किल सेट और एडवांस इंडस्ट्री मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन पर निर्भर रहता है।₹

इंक्रीमेंट पर भी हुई आलोचना

कॉग्निजेंट सालाना इंक्रीमेंट के मुद्दे पर भी तीखी आलोचना का शिकार हुई है। उसने एंप्लॉयीज को 1 फीसदी का भी इंक्रीमेंट दिया है। हालांकि, यह 1 से 5 फीसदी वाला एनुअल इंक्रीमेंट का लोअर बैंड है। अगर किसी एंप्लॉयीज का व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता, तो उसे इतना ही इंक्रीमेंट दिया जाता है।

क्या करती है कॉग्निजेंट?

कॉग्निजेंट टेक्नॉलजी सॉल्यूशंस एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कंसल्टिंग और आईटी सर्विसेज उपलब्ध कराती है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूजर्सी में हैं। कॉग्निजेंट का नाम फॉर्च्यून 2010 की लगातार आठ वर्षों से सबसे तेजी से बढ़ने वाली 100 कंपनियों की सूची में शामिल है।

एलआईसी एजेंट्स की कितनी होती है कमाई, क्या है आवेदन की प्रक्रिया और फायदे?

देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी हर साल लाखों करोड़ का मुनाफा कमाती है। उसके देशभर में लाखों एजेंट भी हैं जिनकी मदद से वह अपना 99 फीसदी इंश्योरेंस बेचती है। इसके बदले उन्हें कमीशन दिया जाता है। आइए जानते हैं कि एलआईसी एजेंट बनने की प्रक्रिया क्या है उनकी कमाई कितनी होती है और एलआईसी एजेंट बनने के फायदे क्या हैं।

नई दिल्ली। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। जून तिमाही में एलआईसी को 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा हुआ। वहीं, पिछले तीन साल में बीमा कंपनी ने शेयर मार्केट से भी तगड़ा प्रॉफिट बनाया और इसके निवेश की मार्केट वैल्यू दोगुनी होकर 15.72 लाख करोड़ रुपये हो गई है। लेकिन, क्या आपको पता है कि लाखों करोड़ का मुनाफा कमाने वाली एलआईसी के एजेंट को कितने पैसे मिलते हैं।

कितनी है एलआईसी एजेंट की कमाई?

सरकार के मालिकाना हक वाली एलआईसी के एजेंट की कमाई राज्यों के हिसाब से अलग-अलग है। एलआईसी एजेंट सबसे अधिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कमाते हैं। वहां पर उनकी महीने की औसत कमाई 20,446 रुपये है। वहीं, हिमाचल प्रदेश में एलआईसी एजेंट की सबसे कम कमाई होती है। महीने के औसतन 10,328 रुपये। अंडमान निकोबार में एलआईसी के 273 और हिमाचल प्रदेश में 12,731 एजेंट हैं। यह जानकारी एलआईसी के डेटा से मिली है, जो उसने वित्त मंत्रालय को उपलब्ध कराया है।

सबसे अधिक एलआईसी एजेंट वाले राज्य

राज्य	एजेंट की संख्या	औसत मासिक कमाई
उत्तर प्रदेश	1.84 लाख	11,887 रुपये
महाराष्ट्र	1.61 लाख	14,931 रुपये
पश्चिम बंगाल	1.19 लाख	13,512 रुपये
तमिलनाडु	87,347	13,444 रुपये
कर्नाटक	81,674	13,265 रुपये
राजस्थान	75,310	13,960 रुपये
मध्य प्रदेश	63,779	11,647 रुपये
दिल्ली-एनसीआर	40,469	15,169 रुपये

देशभर में कितने हैं एलआईसी एजेंट?

LIC के पूरे देश में करीब 14 लाख एजेंट हैं। सबसे अधिक एजेंट यूपी में है, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है। यहां एलआईसी के 1.84 लाख से ज्यादा एजेंट हैं और उनकी महीने की औसत कमाई 11,887 रुपये है। महाराष्ट्र में भी 1.61 लाख एलआईसी एजेंट हैं। वे महीने में औसतन 14,931 रुपये कमाते हैं। पश्चिम बंगाल एजेंट की संख्या के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा सूबा है। यहां पर एलआईसी के करीब 1.2 लाख एजेंट हैं, जो महीने में 13,512 रुपये औसतन कमाते हैं।

क्या होता है एलआईसी एजेंट का काम?

देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी अपने 99 फीसदी इंश्योरेंस एजेंट के माध्यम से ही बेचती है। इसके बदले एजेंट को कमीशन मिलता है। साथ ही, जब तक बीमा चलता है, एजेंट को हर किस्त में से कुछ पैसे बतौर कमीशन मिलते हैं। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि एजेंट को नए से अधिक कमीशन पुराने वाले बीमे से मिलने लगता है।

अमेरिका की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर बढ़ रहा भारतीयों का भरोसा, नए उच्च स्तर पर पहुंचा निवेश

अमेरिका के राजकोषीय विभाग की ओर से जारी डेटा के अनुसार जून के अंत में सरकारी शेयरों में 1.11 ट्रिलियन डॉलर की हिस्सेदारी के साथ जापान शीर्ष पर रहा है। अमेरिका के सरकारी शेयरों में चीन का निवेश 780 .1 अरब डॉलर पहुंच गया है और यह दूसरे स्थान पर रहा है। 741 .5 अरब डॉलर के साथ ब्रिटेन तीसरे स्थान पर रहा। आइए जानते हैं कि भारत किस नंबर पर रहा।

नई दिल्ली। अमेरिकी सरकार की सिक्योरिटीज में भारत का निवेश जून के अंत में 241.9 अरब डॉलर के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह लगातार तीसरा महीना रहा है, जब अमेरिकी सरकार की सिक्योरिटीज में भारत ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इसी वर्ष मई में भारत का निवेश 237.8 अरब डॉलर था। पिछले वर्ष जून में अमेरिकी सिक्योरिटीज में भारत का निवेश 235.4 अरब डॉलर था।

अमेरिका के राजकोषीय विभाग की ओर से जारी डाटा के अनुसार, जून के अंत में सरकारी शेयरों में 1.11 ट्रिलियन डॉलर की हिस्सेदारी के साथ जापान शीर्ष पर रहा है। अमेरिका के सरकारी शेयरों में चीन का निवेश 780.1 अरब डॉलर पहुंच गया है और यह दूसरे स्थान पर रहा है। 741.5 अरब डॉलर के साथ ब्रिटेन तीसरे और 384.2 अरब डॉलर के निवेश के साथ लक्जमबर्ग चौथे स्थान पर रहा है।

अमेरिकी सरकार की सिक्योरिटीज में निवेश करने के मामले में भारत 12वें स्थान पर है। शीर्ष 10 में शामिल अन्य देशों में 274.8 अरब डॉलर के साथ कनाडा पांचवें, 319.4 अरब डॉलर के साथ केमैन आइलैंड छठे, 318 अरब डॉलर के साथ बेल्जियम सातवें, 308 अरब डॉलर के साथ आयरलैंड आठवें, 307.2 अरब डॉलर के साथ फ्रांस नौवें और 287.1 अरब डॉलर के साथ स्विट्जरलैंड 10वें स्थान पर रहा है। 265.9 अरब डॉलर के निवेश के साथ ताइवान 11वें स्थान पर रहा है।

वैश्विक ग्रोथ 3.2 फीसदी रहने का अनुमान

वैश्विक अर्थव्यवस्था महंगाई, भू-राजनीतिक तनाव और अन्य चुनौतियों के बीच घोर अनिश्चितता से जूझ रही है। साथ ही, दुनियाभर के देशों की विकास दर में भी काफी असमानता है। अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ रेट जून तिमाही में 2.8 प्रतिशत सालाना रही, जो 2024 की पहली तिमाही में 1.4 प्रतिशत के मुकाबले अधिक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने जुलाई में जारी अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य के बारे में अपडेटेड रिपोर्ट में चालू वर्ष के लिए वृद्धि दर 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

कोरोना ने अर्थव्यवस्था को किया था तबाह, सप्लाई चेन हुई थी ध्वस्त; मंकीपॉक्स क्या करेगा?

चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस ने दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं का दम निकाल दिया था। चीन अमेरिका ब्रिटेन से लेकर भारत जैसे सभी देशों में सख्त लॉकडाउन था। इससे कारोबारी गतिविधियां ठप हो गई थीं। सप्लाई चेन भी ध्वस्त हो गई थी। अब मंकीपॉक्स के हेल्थ इमरजेंसी घोषित होने के बाद इसी तरह की आशंका जताई जा रही है। आइए जानते हैं कि यह कितना खतरनाक हो सकता है।

नई दिल्ली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने मंकीपॉक्स या एमपॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। मंकीपॉक्स से अफ्रीका महाद्वीप सबसे अधिक प्रभावित है। वहां 10 देशों में अब तक इसके 20 हजार मरीज सामने आ चुके हैं। मंकीपॉक्स भी कोरोना महामारी की तरह संक्रमण से फैलता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में मंकीपॉक्स के मामले मिले हैं। इनमें हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी शामिल है। आइए जानते हैं कि मंकीपॉक्स कितना खतरनाक है और इसका अर्थव्यवस्था, खासकर आयात और निर्यात, पर क्या असर पड़ सकता है।

क्या कोरोना जितना खतरनाक है मंकीपॉक्स?

चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस ने दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं का दम निकाल दिया था। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर भारत जैसे सभी देशों में सख्त लॉकडाउन था। इससे कारोबारी गतिविधियां ठप हो गई थीं। सप्लाई चेन भी ध्वस्त हो गई थी। बेरोजगारी अपने चरम पर थी। अब मंकीपॉक्स के हेल्थ इमरजेंसी घोषित होने के बाद इसी तरह की आशंका जताई जा रही है।

हालांकि, राहत बात यह है कि मंकीपॉक्स फिलहाल कोरोना जितना संक्रामक नहीं है यानी यह उतनी तेजी से नहीं फैल रहा और इसमें मृत्युदर भी कम है। इससे खतरनाक वाले वेरिएंट से संक्रमित होने वाले 100 मरीजों में से सिर्फ 10 की मौत हो रही। वहीं, आम वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में 99.9 फीसदी बच जाते हैं यानी मृत्यु दर तकरीबन न के बराबर है।

किन कारोबारों पर हो सकता है असर?

अगर भारत की बात करें, तो अफ्रीका में निर्यात करने वाले कारोबारी ज्यादा चिंतित हैं। भारतीय निर्यातकों का कहना है कि अगर मंकीपॉक्स की समस्या अधिक विकराल होती है, तो उनके लिए समस्या बढ़ सकती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस (FIEO) के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय का कहना है कि अभी मंकीपॉक्स ज्यादा तेजी से नहीं फैल रहा, लेकिन संक्रमण को देखते हुए निर्यातक परेशान जरूर हैं।

देश के बड़े फुटवियर एक्सपोर्टर में शुमार फरीदा ग्रुप के चेयरमैन रफीक अहमद ने कहा, 'अभी सिचुएशन अलार्मिंग तो नहीं तो है, लेकिन हम बीमारी फैलने से चिंतित है।' एक अन्य एक्सपोर्टर का कहना है कि अभी अफ्रीका में लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। ऐसे में डिमांड-सप्लाई जारी है और हमें भुगतान भी समय पर मिल रहा है। लेकिन, हम मंकीपॉक्स को लेकर चिंतित जरूर हैं और उम्मीद करते हैं कि चीजों जल्दी सही हो जाएं।

एमपॉक्स का असर अभी सीमित

थिंक टैंक- ग्लोब ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) का कहना है कि अभी ग्लोबल ट्रेड पर एमपॉक्स प्रकोप का प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित रहा है, लेकिन हालात पर करीबी नजर बनाए रखने की जरूरत है। जीटीआरआई के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते दुनियाभर में सख्त ट्रैवल बैन लगे। हालांकि, एमपॉक्स से फिलहाल उस तरह के उपाय अपनाने की जरूरत महसूस नहीं हुई है।

हालांकि, श्रीवास्तव ने जोर दिया कि भारत को जरूरी एहतियात बरतने चाहिए और एमपॉक्स से जुड़ी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे व्यापार में किसी भी संभावित व्यवधान को कम किया जा सकेगा। अर्थव्यवस्था पर मंकीपॉक्स के प्रभाव को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी तैयार करने की जरूरत है।

तीन शेयरों में तगड़ी कमाई का मौका, एक्सपर्ट ने दिए बड़े टारगेट प्राइस

बलरामपुर चीनी मिल्स टाटा मोटर्स और ICICI Lombard का डेली और वीकली चार्ट पर प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। इनके ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी तगड़ा उछाल नजर आया है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI भी पॉजिटिव क्रॉसओवर करते हुए बाय सिग्नल दे रहे हैं। ऐसे में इन तीनों स्टॉक्स में आपको कमाई का मौका मिल सकता है। आइए जानते हैं कि टारगेट प्राइस कितना है और स्टॉप लॉस कहां रखना है।

नई दिल्ली। अमेरिका में मंदी की आशंका कम होने के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी का दौर वापस आ गया। शुक्रवार को सेंसेक्स में करीब 2 फीसदी का उछाल दिखा, जो पिछले दो महीने के दौरान एक दिन में इसकी सबसे बड़ी बढ़त है। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे तीन स्टॉक के बारे में बता रहे हैं, जो इस तेजी के दौर में आपकी अच्छी कमाई करा सकते हैं।

बलरामपुर चीनी की बढ़ेगी मिठास

केंद्र सरकार इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाने पर लगातार जोर दे रही है। उसने कीमतों में भी इजाफे का भी संकेत दिया है। इसका फायदा बलरामपुर चीनी मिल्स जैसी कंपनियों को मिलने की उम्मीद है। एलकेपी सिक्योरिटीज ने बलरामपुर चीनी को 525 रुपये के मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह दी है। टारगेट प्राइस 550 से 570 रुपये तक रहेगा। वहीं, स्टॉप लॉस 500 रुपये पर रख सकते हैं।

टाटा मोटर्स भी लगाएगा रेस

टाटा मोटर्स के तिमाही नतीजे और बिक्री के आंकड़े निवेशकों की उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। इससे पिछले दिनों टाटा मोटर्स के शेयरों में कुछ करेक्शन देखने को मिला। लेकिन, अब यह स्टॉक वापस रफ्तार पकड़ चुका है। एलकेपी सिक्योरिटीज की सलाह का है कि टाटा मोटर्स को 1100 रुपये के मौजूदा स्तर पर खरीदा जा सकता है। यह ऊपर की ओर 1160 तक सकता है। वहीं, स्टॉप लॉस 1069 रुपये पर रख सकते हैं।

ICICI Lombard में कमाई

ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में भी कमाई का अच्छा मौका है। इसने डेली चार्ट पर सकारात्मक संकेत दिखाए हैं। ICICI लोम्बार्ड को 2045 रुपये तक आप खरीद सकते हैं। यह 2200 रुपये तक जा सकता है। इसका मतलब कि प्रति शेयर आपको 155 रुपये का मुनाफा हो सकता है। वहीं, स्टॉप लॉस की बात करें, तो आप इसे 1974 रुपये पर रख सकते हैं।

कोलकाता रेप-मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच करेगी सुनवाई

परिवहन विशेष न्यूज

16 अगस्त को एडवोकेट उज्जवल गौड़ और रोहित पांडे ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर कोलकाता घटना का स्वत संज्ञान लेने की अपील की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 20 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट का ये हस्तक्षेप बढ़ते प्रदर्शन और लोगों के दबाव के बीच आया है।

नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप-हत्या मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। 9 अगस्त को हुई इस घटना से देश भर में आक्रोश फैल गया, जिसके कारण देश के कई राज्यों में मेडिकल पेशेवरों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का एलान किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 20 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी।

20 अगस्त को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट का ये हस्तक्षेप बढ़ते प्रदर्शन और लोगों के दबाव के बीच आया है। दरअसल, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले दो वकीलों और तेलंगाना के एक डॉक्टर ने CJI चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया।

CBI के पास हैं मामला

बता दें कि इस मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है। इस हादसे के बाद से भारत के मेडिकल पेशवरों, खासकर महिला डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।

कोलकाता की ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में पड़ा हुआ मिला था। अपराध के सिलसिले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है। हालांकि, पीड़िता के परिवार और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह अपराध सामूहिक बलात्कार था और वे यह सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच की माँग कर रहे हैं।

IMA का देशव्यापी हड़ताल

शव के पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई है कि पीड़िता की मौत से पहले उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। देश में डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने मारे गए डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की है। शनिवार को आईएमए ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान करते हुए सभी गैर-जरूरी चिकित्सा सेवाओं को 24 घंटे के लिए निलंबित कर दिया।

हाथियों के लिए ट्रेन रुकी

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुबनेस्वर् : हाथियों के लिए ट्रेन रुकी । रेलवे के विचार से एक हाथी के बच्चे का जीवन छोटा हो गया। उसके बाद शव की रखवाली मां हथिनी करती है। सुंदरगढ़ बारसुमान रेंज चोरधरा सेक्शन में सुनुबुरु रेलवे जंक्शन के पास एक रेलवे क्रॉसिंग में एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई है। रेलवे साइडिंग अधिकारी और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंच गयी है ।अधिकारी शव के पास नहीं जा सकते क्योंकि हाथी उसकी रखवाली कर रहे हैं। इसके बाद ट्रेन सेवा बंद कर दी गई है ।

सीरवी समाज पारसीगुटा बडेर की नई कार्यकारिणी

सीरवी समाज पारसीगुटा बडेर की नई कार्यकारिणी मौलाली एरिया के सदस्यों को चुना गया जिसमें ढगलाराम सेपटा, चेनाराम परिहा इसर, महिला मंडल सदस्य तुलसी देवी भायल, व चेला पल्ली एरिया सदस्य चेनाराम पंवार, मुलाराम सैणचा, महिला मंडल सदस्य हिणघारी पंवार , परसीगुटा बडेर सचिव किशन सिंह राठौड़, नारायण लाल परिहार, राकेश, भंवरलाल, प्रकाश, डायाराम सोलंकी, लक्ष्मण बर्फा को चुना गया। इस अवसर पर समाज के अनेक गणमान्य बन्धु उपस्थित रहे।

मनीष सिसोदिया की पदयात्रा के साथ संगठन मजबूती का भी चल रहा काम

सुषमा रानी

नई दिल्ली, 18 अगस्त आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली की जनता के साथ मिलकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कमर कस ली है। ''आप'' ने वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आते ही विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। मनीष सिसोदिया का मजबूत साथ मिलने से सभी कार्यकर्ता में भारी उत्साह और आत्मविश्वास से लबालब हैं। 17 महीने बाद जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया पदयात्रा कर सीधे जनता के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं। इसमें उमड़ रही बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों की भारी भीड़ से साफ है कि मनीष सिसोदिया के प्रति लोगों के अंदर दबा प्यार अब उमड़ कर बाहर आ रहा है। मनीष सिसोदिया की पदयात्रा के साथ-साथ संगठन को मजबूत करने का काम भी चल रहा है। मनीष सिसोदिया ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति बनाई है। मनीष सिसोदिया का कहना है कि पदयात्रा को जनता का भारी प्यार और समर्थन मिल रहा है। जिस तरह से भाजपा षड्यंत्र रचकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में बंद कर रही है, उससे दिल्ली की जनता में जनता में भारी आक्रोश है।

मनीष सिसोदिया का आगे कहना है कि भाजपा की केंद्र सरकार से दिल्ली की जनता बेहद नाराज है। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भाजपा ने जेल के अंदर बंद कर रखा है, उसको लेकर जनता में काफी आक्रोश है। केंद्र सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से विधानसभा चुनाव तक हमारे नेताओं को जेल के अंदर बंद रख सके। उन्होंने पहले सत्येंद्र जैन और मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया। उसके बाद हमारे नेता और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को षड्यंत्र रचकर जेल के अंदर बंद कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जमानत दे दी है और मैं बाहर आ गया हूं। अब जल्द ही हमारे नेता अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। भाजपा ने हमें जेल में रखने के लिए हमारे ऊपर ऐसे कानून लगाए जो आतंकवादियों के ऊपर लगाए जाते हैं। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए हमें जेल के अंदर बंद कर दिया, लेकिन हम किसी भी हाल में भाजपा से डरने वाले नहीं है। हम काम की राजनीति करने के लिए आए हैं। जेल से बाहर आकर मैं लगातार लोगों से मिल रहा हूं। मैं बच्चों से मिलने के लिए स्कूलों में जा रहा हूं और पूरी दिल्ली में पदयात्रा निकाल रहा हूं।

उधर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉ. संदीप पाठक का कहना है कि विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी दिल्ली में कई अभियान चला रही है और आने वाले समय में और भी कई अभियान जारी किए जाएंगे। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन जारी है। इस सम्मेलन में स्थानीय विधायक अपने साढे चार साल के कामों की रिपोर्ट जनता के सामने रख रहे हैं। अभी तक 70 विधानसभाओं में से 18 विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का सफल आयोजन हो चुका है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष शामिल होते हैं। इसके अलावा संगठन मंत्री और अन्य पदाधिकारी भी इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे। सोमवार को छतरपुर में होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल होगा। हम हर विधानसभा में जाकर लोगों से जुड़ रहे हैं। उन्हें पिछले साढ़े चार सालों में किए गए अपने काम की जानकारी दे रहे हैं। हम सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं। विधानसभा स्तर पर बूथ मैपिंग का काम भी जारी है।

केंद्रीय मंत्री जोएल ओरम की पत्नी जिंगिया ओरम का निधन हो गया

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुबनेस्वर् : केंद्रीय मंत्री जोएल ओरम की पत्नी जिंगिया ओरम का निधन हो गया। डेंगू के कारण उनका भुवनेश्वर के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा था। जिंगिया का शनिवार रात 10:50 बजे निधन हो गया। मोदी सरकार के ये कैबिनेट मंत्री भी डेंगू से पीड़ित हैं और अपोलो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं ।जिंग्या के निधन की खबर सुनने के बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग के साथ वाचस्पति सूरमा पाढ़ी और अन्य भाजपा नेताओं ने कल देर रात उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपल ने हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का दौरा किया था। बाद में दोनों को डेंगू हो गया। जिंगिया ने 8 मार्च 1987 को जोएल से शादी की। उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु 58 वर्ष थी। दोनों दो बेटियों के माता-पिता हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिंगिया का अंतिम संस्कार सोमवार को उनके पैतृक गांव केंदुडीही में किया जाएगा। जोएल के ओरम सुंदरगढ़ से सांसद हैं । सांसदों की हैट्रिक और मोदी सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री के रूप में दो बार का कार्यकाल। वह वाजपेयी सरकार में भी मंत्री

पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित मेडिकल कॉलेज की घटना हर किसी को परेशान करने वाली है- संजय सिंह

सुषमा रानी

नई दिल्ली, 18 अगस्त आम आदमी पार्टी ने कोलकाता के एक मेडिकल कालेज में महिला डॉक्टर की यौन हिंसा के बाद हत्या को एक बार बेहद संवेदनशील बताते हुए दोषियों को सख्त सजा देने की वकालत की है। ₹आप₹ के वरिष्ठ नेता एवं सांसद संजय सिंह ने रविवार को कहा कि दोषियों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए जो देश में एक नजीर बने। यह घटना हर किसी को परेशान करने वाली है। सीबीआई को चाहिए कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाए और दोषियों को बेहद सख्त सजा दिलवाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ हो रही यौन हिंसा के खिलाफ पूरे देश में एक व्यापक जागरूकता अभियान चलना चाहिए और राजनीतिक दलों को भी ऐसे मामलों में अपनी संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए।

पश्चिम बंगाल स्थित कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य सभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना बेहद दुखदायी और परेशान करने वाली है। उस जूनियर डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब यह मामला सीबीआई के पास है और मुख्य आरोपी की गिरफ़्तारी हो चुकी है। इस मामले से जो लोग भी जुड़े हैं, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही सीबीआई मामले को जल्द से जल्द फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों को सजा दिलाए। इस मामले में जो कार्रवाई हो, वह बेहद ही सख़्त और ऐसी हो कि वह एक उदाहरण बने, जैसा निर्भया के मामले में हुआ था।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा महिलाओं के लिए नए सेफ्टी प्रोग्राम लॉन्च करने के सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर और घर-घर में काम करने की जरूरत है। क्योंकि आज बाहर सड़कों, मेडिकल कॉलेज और अन्य जगहों पर महिलाओं के साथ हिंसा होने के साथ-साथ घरों के अंदर भी उनके साथ यौन हिंसा हो रही है। इसे रोकने के लिए बहुत व्यापक अभियान और जागरुकता फैलाने की जरूरत है। यह बेहद संवेदनशील मामला है। सभी पार्टियों को इसपर राजनीति करने से बचना चाहिए। इसे राजनीति का खेल बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। निश्चित रूप से इसमें सभी को संवेदनशीलता का परिचय देना होगा।

केंद्र की भाजपा सरकार लेटरल इंट्री के जरिए दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है । यूपी की भाजपा सरकार ने शिक्षक भर्ती घोटाले में हजारों छात्रों का जीवन बर्बाद किया।

अभी ये वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जाना चाहते है, अगला नंबर गुरुद्वारा, चर्च, आदिवासी और दलितों की जमीनों पर कब्जा किया जाएगा। भाजपा का मकसद ही जमीनों पर कब्जा करना है। इन्होंने अयोध्या में भारतीय सेना की 13 हजार एकड़ जमीन उठाकर अपने मित्र अडानी को दे दी। इनका मक़सद पूरे देश की संपत्ति को अपने मित्र अदाणी के नाम करना है। यह केवल वक्फ तक रुकने वाला नहीं है। इसलिए सबको सावधान होने की जरूरत है। कल ये लोग मंदिर की जमीन पर बी कब्जा कर सकते हैं। भाजपाई इस देश की सत्ता पर बैठे हुए महाधूर्त लोग हैं। यह इस देश का नहीं अपने दोस्तों का भला करना चाहते हैं। ये लोग किसानों की जमीन नहीं ले पाए। किसान एक साल से धरने पर बैठे हैं, वरना उन तीन काले कानून के जरिए अब तक किसानों की जमीनों कब्जा कर ली गई होती। इन्होंने रेल, सेल की जमीन कब्जा ली, अब ये वक्फ, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, दलितों और आदिवासियों की जमीन कब्जा करेंगे।

संस्कारशाला: राम कथा ज्ञान यज्ञ का महत्व - आचार्य शिवेन्द्र त्रिपाठी के साथ

डॉ. अंकुर शरण

राम निर्भर भारत एक ऐसी यात्रा है जहां श्रीराम के जीवन के हर पहलू को समझने का प्रयास किया जाता है। श्रीराम का जीवन आदर्शों से भरा है, जिसे समझना और अपने जीवन में उतारना कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं।

बचपन से जो रामायण की कहानियां हम दादी-नानी से सुनते आए हैं, वे आज भी हमारे मन-मस्तिष्क में ताज़ा हैं। श्रीराम के आदर्श हमारे दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, विशेषकर युवाओं को इससे अपार प्रेरणा मिल सकती है।

मैं लगातार विभिन्न मंदिरों, पुजारियों और पंडितों से मिलकर श्रीराम के जीवन के बारे में जानने का प्रयास करता रहता हूँ। इसी क्रम में मुझे श्रीराम कथा और उनके यज्ञ के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिसका संक्षिप्त विवरण मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ।

भगवान श्रीराम के जीवन में यज्ञ का महत्व अत्यधिक था। उनके जन्म का आधार ही राजा दशरथ द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ को माना जाता है। यज्ञ ने उनके जीवन में धर्म, कर्तव्य और परोपकार का मार्ग प्रशस्त किया। श्रीराम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर राज्य और समाज की शुद्धि एवं समृद्धि का प्रतीक स्थापित किया। यज्ञ उनके जीवन में ईश्वर की कृपा प्राप्त करने और धर्म की रक्षा के महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा गया है।

श्री राधा कृष्ण मंदिर, परशुराम भवन, सेक्टर 30, फरीदाबाद में आयोजित नौ दिवसीय राम कथा ज्ञान यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हमारे शहर और देश में ऐसी अनेक कथाएं होती रहती हैं। इन कथाओं और सत्संगों में बैठकर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए, अगली बार जब भी आपको ऐसा कोई अवसर मिले, तो अवश्य ही इन कथाओं का आनंद उठाएं और उनके महत्व को समझें।

इस विशेष अवसर पर, आचार्य शिवेन्द्र त्रिपाठी जी ने संस्कारशाला के माध्यम से राम कथा और यज्ञ के महत्व पर अपने विचार साझा किए।

राम कथा का महत्व:

आचार्य शिवेन्द्र त्रिपाठी जी के अनुसार, राम कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को दिशा देने वाली एक प्रेरणादायक गाथा है। रामायण में भगवान श्रीराम के जीवन और उनके आदर्शों का वर्णन है, जो हमें सत्य, धर्म, और कर्तव्य पालन की प्रेरणा देते हैं। राम कथा के माध्यम से हम अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को स्थापित कर सकते हैं और एक उत्तम समाज का निर्माण कर सकते हैं। रामायण हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हमें अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होना चाहिए और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए।

ज्ञान यज्ञ का महत्व:

ज्ञान यज्ञ का उद्देश्य केवल कथा सुनना या पढ़ना नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से हम अपने अंदर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के अज्ञान को दूर कर ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। आचार्य शिवेन्द्र त्रिपाठी जी ने बताया कि यज्ञ का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर सद्गुणों का विकास करने और नकारात्मकताओं को समाप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। यज्ञ से वातावरण की शुद्धि होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

राम कथा और यज्ञ का संगम:

राम कथा और यज्ञ का संयुक्त आयोजन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। राम कथा के माध्यम से हम श्रीराम के आदर्शों को अपने जीवन में उतार सकते हैं, जबकि यज्ञ के माध्यम से हम अपने जीवन को शुद्ध और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार के आयोजन से हमें न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि हम अपने जीवन में धर्म, संस्कार, और सद्गुणों का विकास भी कर सकते हैं।

आचार्य शिवेन्द्र त्रिपाठी जी के अनुसार, राम कथा और यज्ञ का आयोजन हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह हमें आत्मशुद्धि की ओर ले जाता है और हमारे जीवन को नए दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा देता है।

राम कथा सुनकर उन्हें जीवंत करना और अपने जीवन में उन सद्विचारों को उतारना भी एक लक्ष्य होना चाहिए। जब आप कुछ सुनते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो वह आपके मन-मस्तिष्क में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है। यदि आप ऐसे मधुर वचनों को लिखते हैं और उन पर मनन करते हैं, तो धीरे-धीरे वे आपकी आदतों में शामिल हो जाते हैं।

यज्ञ में बैठकर कथा सुनना हमारे सनातन धर्म की एक प्राचीन विधि है। ऐसे कथाओं और विचारधाराओं से हम सन्मार्ग पर चल सकते हैं। यह लोकतंत्र है—सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन यदि आपके पास संस्कार हैं, तो वे आपको मूल्यवान और बलवान बनाएंगे। तभी आप सशक्त होकर राष्ट्रहित के लिए आगे बढ़ पाएंगे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023